

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16, 1995/भाद्र 25, 1917

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1995/BHADRA 25, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government  
of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

न्यायिक अनुभाग

सूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

Judicial Section

NOTICE

New Delhi, the 21st August, 1995

का.आ. 2444.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के  
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती  
है कि श्री राजेन्द्र झा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त  
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए  
दिया है कि उसे पटना (बिहार) में व्यवसाय करने के लिए  
नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस  
सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे  
पास भेजा जाए।

[सं. 5 (59)/95—न्यायिक]  
पी. सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 2444.—Notice is hereby given by the Competent  
Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules,  
1956 that application has been made to the said Authority,  
under Rule 4 of the said Rules, by Shri Rajendra Jha, Ad-  
vocate for appointment as a Notary to practise in Patna  
(Bihar).

2. Any objection to the appointment of the said person  
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned  
within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(59)/95-Judl.]  
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

का.आ. 2445.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राज बाला मिश्रा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(139)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 21st August, 1995

S.O. 2445.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Ms. Raj Bala Mishra, Advocate for appointment as a Notary to practise in Delhi, i.e. NCT of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice

[No. F. 5(139)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

का.आ. 2446.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जनक राज शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मिरावाड़ा जिला (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(140)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 21st August, 1995

S.O. 2446.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Janak Rai Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Ambala Distt. (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(140)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1995

का.आ. 2447.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राजबीर त्यागी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(143)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 22nd August, 1995

S.O. 2447.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Rajbir Tyagi, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Ghaziabad (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice

[No. F. 5(143)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1995

का.आ. 2448.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हिरालाल महापात्रा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मिदनापुर जज कोर्ट मिरावाड़ा (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(144)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 22nd August, 1995

S.O. 2448.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules by Shri Hiralal Mahapatra, Advocate for appointment as a Notary to practise in Midnapore Judges Court, Midnapore (West Bengal)

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(144)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## सूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1995

का.प्रा. 2449.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6A के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री व्यास कल्पना चिमनलाल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अथवा नाथन कवास हजीरा प्रोजेक्ट गुजरात में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(145)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 22nd August, 1995

S.O. 2449—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Vyasa Kalpana Chiman Lal, Advocate for appointment as a Notary to practise in Athwa Lines Kawas Hazira Project (Gujarat Athwa).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(145)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## सूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1995

का.प्रा. 2450.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6A के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हरबंस लाल मिगलानी एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे श्रीगंगा नगर (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(146)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 22nd August, 1995

S.O. 2450.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Harbans Lal Miglani, Advocate for appointment as a Notary to practise in Sriganaganagar (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(146)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1995

का.प्रा. 2451.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6A के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री इन्दर मोहन मल्होत्रा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(147)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 23rd August, 1995

S.O. 2451.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Inder Mohan Malhotra, Advocate for appointment as a Notary to practise in Delhi, i.e. NCT of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(147)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1995

का.प्रा. 2452.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6A के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री चन्द्र प्रकाश दीक्षित, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मेरठ जिला (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(148)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 23rd August, 1995

S.O. 2452.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Chandra Prakash Dixit, Advocate for appointment as a Notary to practise in District Meerut in U.P.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(148)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1995

का. आ. 2453.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट के उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे उत्तरी दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(149)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 23rd August, 1995

S.O. 2453.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Ashok Kumar Sharma Advocate for appointment as a Notary to practise in North Delhi N.C.T. of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(149)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1995

का. आ. 2454.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बलराम सिन्हा राय, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे चिन सुरहा कोर्ट, जिला हुगली, (प. बंगाल) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(150)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 23rd August, 1995

S.O. 2454.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Balram Sinha Roy Advocate for appointment as a Notary to practise in Chinsurha Court, Distt. Hooghly (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(150)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1995

का. आ. 2455.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्रीमति आश्विनी रविन्द्र, घटनेकर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे विश्रामवाडी पुणे (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(151)/95-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 23rd August, 1995

S.O. 2455.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Smt. Ashwini Ravendra Ghatrekar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Vishramwadi, Pune (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(151)/95-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1995

का. आ. 2456.—चूंकि का. सं. 801/32/93-पिट एन डीपीएस दिनांक 12-8-93 के अन्तर्गत संयुक्त सचिव भारत सरकार को स्वापक औषध तथा मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 के खंड 3 के उपखंड (i) के अन्तर्गत अवैध व्यापार को रोकने के लिए विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, निदेश देते हैं कि श्री गनी इब्राहिम पुत्र श्री सुलतान इब्राहिम निवासी 5/59 मिडिल स्ट्रीट वाली नोकाम जिला रामानंद तमिलनाडु का स्वापक औषधों को भारत में निर्यात करने में शामिल होने को रोकने के लिए तजरबंद किया जाए तथा केन्द्रीय कारागार मद्रास (तमिलनाडु) में हिरासत में रखा जाए।

2. जबकि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार होने अथवा अपने आपको छिपाने की चेष्टा कर रहा है ताकि आदेश को कार्यान्वित न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम के खंड-8 उपखंड (i) क्लॉज (ख) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उपर्युक्त व्यक्ति इस आदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के 10 दिनों के भीतर

सहायक निदेशक/वरिष्ठ (आयुधमा अधिकारी) बी आर आई  
सेलम एकक नं. 3 चर्च कालोनी अलोथुराई रोड मूथूर तिवी  
62007 के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 801/32/93-पीआईटीएनडीपीएस]  
बी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 17th August, 1995

S.O. 2456.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801/32,93-PITNDPS dated 17-8-1993 under the said sub-section directing that Shri Gani Ibrahim S/o Shri Sultan Ibrahim, R/o 559, Middle Street, Valinokkam, Ramnad District, Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras (Tamil Nadu) with a view to preventing him from engaging in export from India of narcotic drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Asstt. Director/Senior Intelligence Officer, DRI, Regional Unit, No. 3, Church Colony, Allothurai Road, Puthur Trichy-620017, within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801/32/93-PITNDPS]  
B. K. ARORA, Under Secy.

(आयुध कार्य विभाग)

(वैक्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1995

का.आ. 2457.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उप-बंध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री जीतेन्द्र श्रीधर बैलूर, विशेष सहायक, बैंक आफ इंडिया, अंधेरी वेस्ट ब्रांच 28, एस. वी. रोड, अंधेरी (वे.) बम्बई को दिनांक 25 अगस्त, 1995 से 24 अगस्त, 1998 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे बैंक आफ इंडिया के एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते

हैं, इसमें से जो पहले हो, बैंक आफ इंडिया के निदेशक बॉर्ड में निवेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 15/13/94 - आई. आर.]

एस. के. बत्रा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 25th August, 1995

S.O. 2457.—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of Clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Jitendra Shridhar Bailur, Special Assistant, Bank of India, Andheri West Branch, 28, S. V. Road, Andheri (W), Bombay as a Director on the Board of Directors of Bank of India for a period of three years with effect from 25th August, 1995 to 24th August, 1998 or until he ceased to be an employee of Bank of India whichever is earlier.

[F. No. 15/13/94-IR]  
S. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.आ. 2458.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डा. सी. रंगाराजन को 22 दिसम्बर, 1995 से आरम्भ होकर 21 दिसम्बर 1996 को समाप्त होने वाली और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर पुनः नियुक्ति करती है।

[सं. एफ. 7/26/92 - बी. आ. 1]

वाई. वी. रेड्डी, सचिव

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2458.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-appoints Dr. C. Rangarajan as Governor of the Reserve Bank of India for a further period commencing on 22nd December, 1995 and ending with 21st December, 1996.

[No. 7/26/92-BO.1]  
Y. V. REDDY, Secy.

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1995

का.आ. 2459.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड 'ख' के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं।

## अनुसूची

क्रम संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष संख्या	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तारीख
1	2	3
4		
1. आईएस 371 : 1979	संशोधन सं. 5, जुलाई 1995	1995 07 31
2. आईएस 997 : 1973	संशोधन सं. 1, अप्रैल 1995	1995 04 30
3. आईएस 1110 : 1990	संशोधन सं. 1, मई 1995	1995 05 31
4. आईएस 1170 : 1992	संशोधन सं. 1, मई 1995	1995 05 31
5. आईएस 1470 : 1990	संशोधन सं. 1, मई 1995	1995 05 31
6. आईएस 1783 (भाग 1) : 1993	संशोधन सं. 1, जुलाई 1995	1995 07 31
7. आईएस 891 (भाग 2) : 1993	संशोधन सं. 1, जून 1995	1995 06 30
8. आईएस 3257 : 1985	संशोधन सं. 1, जून 1995	1995 06 30
9. आईएस 3224 : 1985	संशोधन संख्या 1, जुलाई, 1995	1995 07 31
10. आईएस 4283 : 1981	संशोधन संख्या 2, जून 1995	1995 06 30
11. आईएस 4351 : 1976	संशोधन संख्या 2, जून 1995	1995 06 30
12. आईएस 4615 : 1968	संशोधन संख्या 7, जून 1995	1995 06 30
13. आईएस 7253 : 1974	संशोधन सं. 5, जून 1995	1995 06 30
14. आईएस 8500 : 1991	संशोधन संख्या 2, मई 1995	1995 05 31
15. आईएस 8805 (भाग 1) : 1978	संशोधन संख्या 3, जून 1995	1995 06 30
16. आईएस 9537 (भाग 1) : 1980	संशोधन संख्या 1, जुलाई, 1995	1995 07 31
17. आईएस 10325 : 1989	संशोधन संख्या 3, जून 1995	1995 06 30
18. आईएस 10339 : 1988	संशोधन संख्या 1, जून 1995	1995 06 30
19. आईएस 10633 : 1986	संशोधन संख्या 3, अप्रैल 1995	1995 04 30

1	2	3	4
20. आईएस 10633 : 1986	संशोधन संख्या 4, मई 1995	1995 05 31	
21. आईएस 11081 : 1993	संशोधन संख्या 1, जुलाई 1995	1995 07 31	
22. आईएस 12484 : 1988	संशोधन संख्या 1, जून 1995	1995 06 30	
23. आईएस 12732 : 1989	संशोधन संख्या 1, जुलाई, 1995	1995 07 31	
24. आईएस 13225 : 1992	संशोधन संख्या 1, मई 1995	1995 05 31	

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, पानक भवन, 9 बहादुर शाह जकर मार्ग, नई दिल्ली 110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा मद्रास और भाषा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, विरभन्नापुरम, लखनऊ, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में बिक्री हेतु उपलब्ध है।

[स. के. प्रसि / 13 : 45]

एस.के.कर्मकार और सहायिदेशक

## MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

### BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 24th August, 1995

S.O. 2459.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the Schedule hereto annexed, has/have been issued.

### SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standard amended	No. and date of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 371 : 1979	Amendment No. 5, July, 1995	1995-07-31
2.	IS 997 : 1973	Amendment No. 1, April, 1995	1995-04-30
3.	IS 1110 : 1990	Amendment No. 1, May, 1995	1995-05-31
4.	IS 1170 : 1992	Amendment No. 1, May, 1995	1995-05-31
5.	IS 1470 : 1990	Amendment No. 1, May, 1995	1995-05-31
6.	IS 1783 (Part 1) : 1993	Amendment No. 1, July, 1995	1995-07-31
7.	IS 1891 (Part 2) : 1993	Amendment No. 1, June, 1995	1995-06-30

1	2	3	4
8.	IS 3257 : 1985	Amendment No. 1, June, 1995	1995-06-30
9.	IS 3424 : 1985	Amendment No. 1, July, 1995	1995-07-31
10.	IS 4283 : 1981	Amendment No. 2, June, 1995	1995-06-30
11.	IS 4351 : 1976	Amendment No. 2, June, 1995	1995-06-30
12.	IS 4615 : 1968	Amendment No. 7, June, 1995	1995-06-30
13.	IS 7253 : 1974	Amendment No. 5, June, 1995	1995-06-30
14.	IS 8500 : 1991	Amendment No. 2, May, 1995	1995-05-31
15.	IS 8805 (Part 1) : 1978	Amendment No. 3, June, 1995	1995-06-30
16.	IS 9537 (Part 1) : 1980	Amendment No. 1, July, 1995	1995-07-31
17.	IS 10325 : 1989	Amendment No. 3, June, 1995	1995-06-30
18.	IS 10339 : 1988	Amendment No. 1, June, 1995	1995-06-30
19.	IS 10633 : 1986	Amendment No. 3, April, 1995	1995-04-30
20.	IS 10633 : 1986	Amendment No. 4, May, 1995	1995-05-31
21.	IS 11081 : 1993	Amendment No. 1, July, 1995	1995-07-31
22.	IS 12484 : 1988	Amendment No. 1, June, 1995	1995-06-30
23.	IS 12732 : 1989	Amendment No. 1, July 1995	1995-07-31
24.	IS 13225 : 1992	Amendment No. 1, May 1995	1995-05-31

Copies of these amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices : New Delhi, Calcutta, Chandigarh, Madras and Bombay and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Patna, Thiruvananthpuram.

[No. CMD/13 : 5]

S.K. KARMAKAR, Addl. Director General

सागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और  
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995

का. मा. 2460.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की

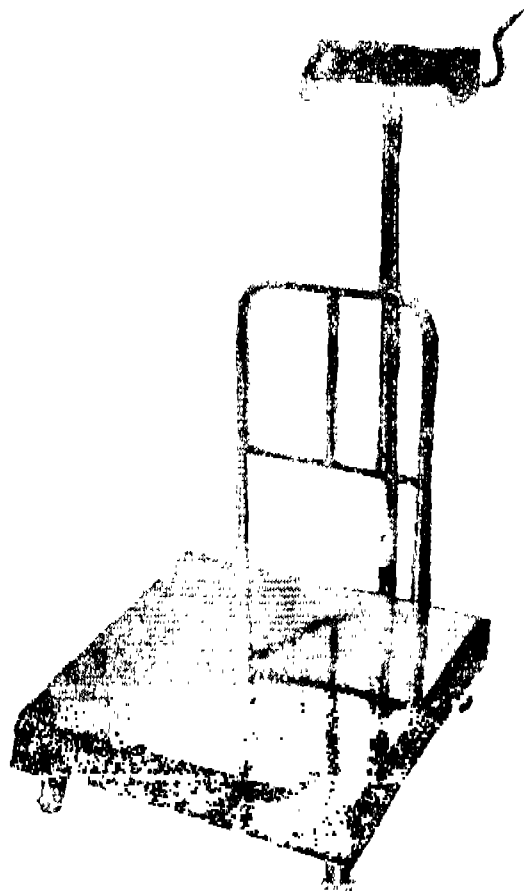
संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त काम करता रहेगा ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एम. आई. पी. सिरीज वर्ग 3 टाइप के स्वतः सूचक, गैर-स्वचालित प्लेटफार्म तोलन उपकरण के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स ह्मात्रे इंडस्ट्रीज, बड़ौदा द्वारा किया गया है और जिसे



अनुमोदन विहित आई. एन. डी. 09/94/76 समनुवर्धित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है

New Delhi, the 5th September, 1995



माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का प्लेट फार्म तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 20 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारग्राही धारिवक प्लेट का है जिसका पार्श्व 450×450 मिलीमीटर है। सात खंडीय प्रकाश उत्सर्जन डायोड संपदश तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के विद्युत प्रवाय पर प्रचालित होता है।

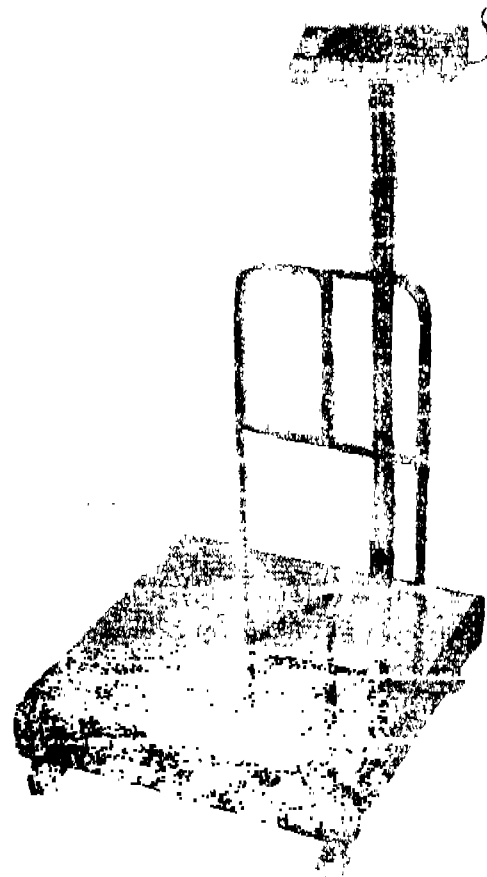
आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 50 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी सीरीज के कार्यकरण वाले प्लेट फार्म तोलन उपकरण भी होंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(41)/94]  
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

S.O. 2460.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic platform weighing instrument type MIP series class III (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Mhatre Industries, Boroda and which is assigned the approval mark IND/09/94/76;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) platform weighing instrument with a maximum capacity of 100 kg and minimum capacity of 400 gram. The verification scale interval (e) is 20 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of metallic plate of sides 450×450 millimetre. The 7 segment LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz power supply.



figure

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the platform weighing instrument of similar make, accuracy and performance of the same series with maximum capacity of 50 kg, 150 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg, 1000 kg and 2000 kg manufactured by the same manufacturer in

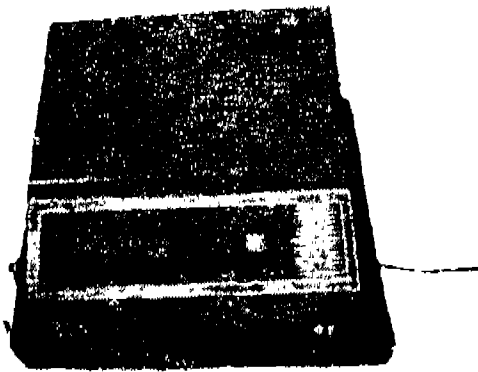
accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(41)/94]  
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995

का. प्र. 2461.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि उक्त माडल लगानार प्रयोग की श्रद्धा में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त काम करता रहेगा ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एम. आई. मीरीज वर्ग 3 टाइप के स्वत. सूचक, गैर-स्व-चालित टेबल टॉप तोलन उपकरण के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स ह्.मात्रे इंडस्ट्रीज, बड़ौदा द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी. 09/94/77 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है ;



माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का टेबल टॉप तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 5 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है। स्थापित मापमान अंतर (ई) 1 ग्राम है। इसमें एक टैयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टैयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारग्राही धात्विक प्लेट का है जिसका पार्श्व 230×250 मिली मीटर है। मात खंडीय प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री

से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 0.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी मीरीज के कार्यकरण वाले प्लेटफार्म तोलन उपकरण भी होंगे।

[का. स. इन्स्यू. एम. 21(41)/94]]

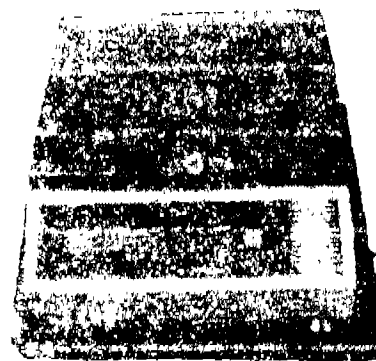
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th September, 1995

S.O. 2461.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating non-automatic Table top weighing instrument type MI series class III (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Mhatre Industries, Boroda and which is assigned the approval mark IND/09/94/77;

The Model (see figure) is a Medium accuracy (accuracy class III) table top weighing instrument with a maximum capacity of 5 kg and minimum capacity of 20 gram. The verification scale interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of metallic plate of sides 230×250 millimetre. The 7 segment I.E.D display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz power supply.



figure

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the platform weighing instrument of similar make, accuracy and performance of the same series with maximum capacity of 0.5 kg, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg and 30 kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(41)/94]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

## कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1995

का. आ. 2462.—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनाए गए स्थायी वित्त समिति के विनियम 2 (iv) के अनुसरण में तथा कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 की धारा 7(2) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्यों को इस निकाय द्वारा 28-6-1995 से 27-6-1996 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा यदि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी अवधि खत्म होने तक नहीं कर लिया जाता, स्थायी वित्त समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है —

1. डा. सुखदेव सिंह,  
मकान नं. 419,  
सेक्टर 38-ए,  
चंडीगढ़-160014
2. डा. पी. एस. लाम्बा,  
51, डिफेंस कॉलोनी,  
हिसार-125001 (हरियाणा)
3. डा. आर. पी. एस. त्यागी,  
कुलपति,  
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,  
पालमपुर-176062 (हि. प्र.)
4. श्री एम. एस. मुरजेवाला,  
सदस्य, राज्य सभा,  
मकान सं. 495, सेक्टर-6,  
पंचकुला, जिला—अम्बाला,  
हरियाणा  
ए-बी 89, शाहजहा रोड,  
नई दिल्ली
5. श्री डी. एस. अनन्त,  
प्लान्टर,  
सं. 513, 10 बी. मेन  
डब्ल्यू. सी. आर., III स्टेज, iv ब्लॉक,  
अशादीयवर नगर, पोस्ट आफिस के पीछे,  
बंगलौर-560079
6. डा. आर. एन. वर्मा,  
निदेशक,  
राष्ट्रीय जुम्बी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान,  
अम्बाघाट,  
सोलन-173213 (हि. प्र.)
7. डा. हरशजन सिंह,  
प्रयोगना निदेशक,

राष्ट्रीय मीठा पानी मासिकी अनुसंधान केन्द्र,  
शिल्वा हिल्स नर्सरी,  
रूप नगर, पी. बी. स. 28,  
हल्द्वानी-263229  
जिला—नैनीताल ।

[फा. सं. 6(1)/95-सी. एस. सी.]

जी. एम. साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(Department of Agricultural Research & Education)  
(Indian Council of Agricultural Research)  
New Delhi, the 24th August, 1995

S.O. 2462.—In pursuance of Regulation 2(iv) of the Standing Finance Committee Regulations, framed by the Indian Council of Agricultural Research and in pursuance of provision contained in Section 7(2) of the A. P. Cess Act, 1940, the Governing Body has elected the following Members to the Standing Finance Committee for a period of one year with effect from 28-6-1995 to 27-6-1996 or in case their successor have not been duly elected before the expiry of the term until their election.

1. Dr. Sukhdev Singh,  
House No. 419,  
Sector 38-A,  
Chandigarh-160014.
2. Dr. P. S. Lamba,  
51, Defence Colony,  
Hissar-125001 (Haryana).
3. Dr. R. P. S. Tyagi,  
Vice-Chancellor,  
Himachal Pradesh Krishi  
Vishwa Vidyalyaya,  
Palampur-176062 (H.P.).
4. Shri S. S. Surjewala,  
Member, Rajya Sabha,  
House No. 495, Sector-6,  
Panchkula, Distt. Ambala,  
Haryana  
A-B 89, Shahjahan Road,  
New Delhi.
5. Shri D. S. Ananth,  
Planter,  
No. 513, 10th B. Main  
W.C.R., III Stage, IV Block,  
Bashavshwar Nagar. Behind, P.O.  
Bangalore-560079.
6. Dr. R. N. Verma,  
Director,  
National Centre for Mushroom.  
Research & Training,  
Chambaghat,  
Solan-173213 (H.P.).
7. Dr. Harbajan Singh,  
Project Director,  
National Research Centre on  
Coldwater Fisheries, Shilwa.  
Hills Nursery, Roop Nagar,  
P.B. No. 28, Haldwani-263129,  
Distt. Nainital.

[F. No. 6(1)/95-CSC]  
G. S. SAHNI, Jt. Secy

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का. आ. 2463.—लोक परिमर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे तालिका के कालम-1 में वर्णित अधिकारी को, सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम

के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा और उक्त अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा उक्त तालिका के कालम-2 संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट लोक परिसरों बाबत अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर सम्पदा अधिकारी को सौंपे गए दायित्वों को निभाएगा।

## तालिका

अधिकारी का पदनाम	लोक परिसर की श्रेणी व क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
------------------	---

उप सचिव, पंजाब सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर पंजाब सरकार के स्वामित्व वाले तथा उसके द्वारा नियंत्रित सभी रिहायशी और गैर-रिहायशी परिसर।
--	--

[संख्या आई-11016/5/95-एच-II)]

एच. के. घोष, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Department of Urban Employment and Poverty Alleviation)

New Delhi, the 28th August, 1995.

S.O.2463.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being Gazetted Officer of the Government, to be estate officer for the purpose of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Category of public premises and local limits jurisdiction
(1)	(2)
Deputy Secretary to Government of Punjab,	All residential and non-residential premises

(1)

Department of Welfare of Scheduled Castes and Backward classes, Chandigarh.

(2)

owned and controlled by the Government of Punjab within the local limits of the Union territory of Chandigarh.

[No. I-11016/5/95-H. II]  
H.K. GHOSH, Under Secy.नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय  
(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1995

विषय:—होटल ऋणों पर व्याज इमदाद।

का. आ. 2464.—राष्ट्रपति ने व्याज इमदाद स्कीम को भारतीय पर्यटन विल निगम, भारतीय औद्योगिक विल निगम तथा राज्य वित्त निगमों के अलावा अनुमोदित 1, 2, 3 सितारा होटल परियोजनाओं (दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के महानगरों की परियोजनाओं को छोड़कर) तथा हरिटेज होटल परियोजनाओं के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा स्वीकृत ऋणों पर भी उसी तरह से लागू किया है।

2. व्याज इमदाद की शर्तें वहीं रहेंगी जैसाकि इस विभाग की दिनांक 25-8-92 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित की गई हैं।

3. उपर्युक्त आदेश इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख अर्थात् 1 अगस्त, 1995 से लागू होंगे।

4. इन आदेशों को एकीकृत वित्त की दिनांक 13-7-95 के अनौपचारिक टिप्पणी सं. 1570/एफ 11/95 के तहत उनकी सहमति से जारी किया गया है।

[सं. 4-टी एच. II(2)/88]

ए. के. सूद, अवर सचिव

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION &amp; TOURISM

(Department of Tourism)

New Delhi, the 1st August, 1995

SUBJECT : Interest Subsidy on Hotel Loans

S.O. 2464.—The President of India is pleased to extend the scheme of Interest Subsidy on the loans granted to the approved 1, 2, 3 Star Hotel Projects (except in the Metropolitan cities of Delhi, Calcutta, Bombay & Madras) and Heritage Hotels Projects by the State Industrial Development Corporations as well in addition to TFCL, IFCL and State Financial Corporations.

2. The terms and conditions for interest subsidy remain the same as notified under Notification dated 25th August, 1992.

3. The above orders shall come in force with effect from the date of this Notification i.e. 1st August, 1995.

4. These orders are issued with the concurrence of Integrated Finance vide their U.O. No. 1570/FII/95 dated 13th July, 1995.

[No. 4-TH. II(2)/88]

A. K. SOOD, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

का. मा. 2465.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जे. एन. चटर्जी एंड अदर्स के प्रवर्धन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29011/4/86-डी-III(बी)/डी-III(ए)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st August, 1995

S.O. 2465.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of J. N. Chatterjee & Others and their workmen, which has received by the Central Government on the 16th August, 1995.

[No. L-29011/4/86-D.III(B)/D-III(A)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 125 of 1988

PARTIES:

Employers in relation to the management of J. N. Chatterjee &amp; Others.

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. Justice K. C. Jagadeb Roy, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Management—Mr. S. Ghosh, Advocate.

On behalf of Workmen—None.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Quarry.

AWARD

By Order No. L-29011(4)/86-D.III(B)/D.III(A) dated 26th August, 1987, the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and sub-section (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the following demands raised by Kamalpur Quarry Mazdoor Union, P.O. Kamalpur, Durgapur-4 District Burdwan, W.B. on the employers listed in the schedule are justified. If so, to what relief they are entitled?”

1. Demand for payment of wages/remuneration to the workers engaged on removal of earth above the seam of gravel.
2. Issuing of appointment letter to each and every person employed indicating the date of appointment designation and rate of wages.
3. Demand for paid holidays falling on Republic Day, May Day, Netaji's Birthday, Gandhiji Birthday & Independence day.
4. Demanding adoption of Group Insurance System for the workers alternatively payment of compensation

to the workers who may be victim of accident during working hours irrespective of applicability of the provisions of the workman compensations Act.

5. Payment of House rent at the rate of 15 per cent P.M. of their wages where no standard housing facilities provided.
6. Demanding provisions of services of qualified doctor and provision of medicine for the workers and every members from the family of the workers and reimbursement of medical expenses incurred by workmen.
7. Introduction/extension of Provident Fund Scheme to the gravel quarry workers where the statute is not applicable.

## List of Employers

1. M/s. J. N. Chatterjee & Others represented through Shri Madhusudan Mishra, P.O. Kamalpur via Durgapur-4, District Burdwan (W. Bengal).
2. M/s. J. N. Chatterjee & others represented by M/s Shyam & Banerjee P.O. Kamalpur via Durgapur-4, District Burdwan (W.B.).
3. M/s. Shaktipada Chatterjee represented through Shri Ashoka Chatterjee, P.O. Kamalpur via Durgapur-4, District Burdwan.
4. M/s. L. C. Kapoor, P.O. Kamalpur via Durgapur-4, District Burdwan.
5. M/s. Biswas Brothers, P.O. Dhabani, via Durgapur-4, District Burdwan (W.B.).
6. M/s. Biswas Company, P.O. Dhabani, Via Durgapur-4, District Burdwan (W.B.).

2. This is a reference case of the year 1988. The written statement had been filed by the workmen, but out of the seven employers enumerated in the order of reference, only three of them namely M/s. Biswas Brothers and M/s. Biswas Company and M/s. L. C. Kapoor filed their written statements in April, 1993

3. Though the management was represented by Mr. S. Ghosh, learned counsel, the workmen failed to file their letter of authority in favour of any one till today.

4. Only one witness was examined on behalf of the workmen on 13th October, 1992 whose examination in chief was concluded on the same day. He could not be cross-examined on that day and never presented himself before the Tribunal on any other subsequent dates for his cross-examination. His statement in chief therefore cannot be treated as legal evidence. No other witness had been examined before the Tribunal on behalf of the workmen.

5. Even though notice of the proceeding had been received by the Union on 19th January, 1995, it took no steps to appear before the Tribunal and lead its evidence, even though the case was adjourned for several dates for the purpose. Thereafter when the case was called on 15th June, 1995, it was stated by Mr. Ghosh, learned counsel appearing for the management that the matter had been settled out of court on 4th May, 1994 and as such the workmen did not choose to take any step in the case. Though the management had undertaken to file copy of the Memorandum of such settlement, the case was adjourned on 21st December, 1994 but no such memorandum of settlement was filed. The Tribunal therefore fixed the case to 10th July, 1995 for the workmen to produce their evidence and file letter of authority in favour of their representative. In spite of that none appeared on 10th July, 1995.

6. Since no reference can be adjudicated without any evidence on record and the workmen who have a right to begin, have failed to lead any evidence and the only evidence that had been intended to be led is that of WW-1 which is of no avail, since the witness did not present himself for his cross-examination. In the eye of law therefore there is no evidence available in the record from the side of the workmen. No material is available before me to hold that the workmen were unfairly prevented to appear

before this Tribunal to canvass their grievance or were forced to give up their grievance unfairly. I accordingly held that the workmen have given up their demands in this reference case. I therefore pass a "No Dispute" Award.

The reference is answered accordingly.  
Dated, Calcutta.

The 11th July, 1995.

K. C. JAGADFB ROY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

का. आ. 2466.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ बड़ोदा के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेशों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, उदयपुर के पंच-पट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/5/93/आई. आर. बी.-2]

ब्रज मोहन, डस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1995

S.O. 2466.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Udaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 16th August, 1995.

[No. L-12012/05/93-IR(B-11)]  
BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर  
(राज.) पीठासीन अधिकारी : श्री ओम प्रकाश गुप्ता,  
आर० एच० जे० एम०

प्रकरण संख्या

(3 सन 93)

श्री ध्रुव शंकर व्यास पुत्र श्री लाल शंकर व्यास निवास  
मुन्दनपुर जिला बांसवाला

प्रार्थी

बनाम

श्री क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक आफ बड़ोदा, चित्तौड़गढ़ रेल्वे स्टेशन  
के पास चित्तौड़गढ़

—विपक्षी

उपस्थित:

श्री एम० पी० जोशी, प्रार्थी की ओर से।

श्री बी० एच० गुप्ता, विपक्षी की ओर से।

दिनांक 1-8-1995

पंचाट

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जरिये क्रमांक 12012/5/93/आई० आर० बी०-2 दिनांक 10-8-93 द्वारा निम्न निवादिन निम्न शास्त्रे अभिविधरण 8म न्यायालय को प्रेषित किया गया।

Whether the action of the management of Bank of Baroda Chittorgarh in dismissing the services of Shri Dhruv Shankar s/o Lalshankar Vyas w.c.f. 27-9-86 is justified? If not, to what relief is the workman entitled to?

स्टेटमेंट आफ फ्लेम में उल्लेख किया है कि प्रार्थी, विपक्षी संस्थान के अधीन 7-9-72 से पाच में व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगा था और 1-12-77 में सिपिक के पद पर चयनित किया गया। दिनांक 27-9-86 को प्रार्थी को निलम्बित किया गया और 5900/- रुपये के गबन का आरोप लगाया। विपक्षी द्वारा जांच आयोजित की गई और उसमें पुनः सेवा में लिये जाने का आश्वासन दिया। अतः झूठा ही प्रार्थी में आरोप को स्वीकार करने के लिये मजबूर किया। यह भी उल्लेख किया है कि अधिकारी द्वारा 1350 रुपये प्रार्थी से वसूल किये तथा उस समय कार्यरत लेखापाल श्री एम० के० गुप्ता, से भी इतनी ही राशि की रकम वसूल कर जमा की गई, अर्थात् वे भी शोषी थे। परन्तु जांच कार्यवाही में भेदभाव का स्वरूप अपनाते हुये प्रार्थी को 14-5-88 में सेवा से पृथक कर दिया और एम० के० गुप्ता अभी भी सेवा में है। यह भी उल्लेख किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान एफ० 25 की पालना नहीं की गई। सारी जांच कार्यवाही नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांत के विपरीत की गई और षड्यंत्र रचकर झूठे आरोपों को स्वीकारने के आधार पर नीकरी से पृथक कर दिया। अतः सम्पूर्ण बकाया वेतन सहित सेवा की निरन्तरता के साथ पुनः सेवा में बहाल किये जाने का प्रार्थना की है।

जवाब में विपक्षी संस्थान ने प्रार्थी का 7-9-72 के आदेशानुसार सब आडिनेन्ट कैंडिड में प्रियात कम वाचमन के पद पर नियोजन में होने व 29-11-77 में चयनित होकर 1-12-77 से प्रार्थी का क्लर्क केंद्र परान्त/पदस्थापित होना स्वीकार किया है और इसके आदेश प्रदर्श ए-1 व प्रदर्श-2 पेश किये हैं। यह भी उल्लेख किया है कि प्रार्थी बैंक आफ बड़ोदा की तलवाड़ा शाखा में 3-3-86 को है केशियर के पद पर नियोजित था और ब्रांच की केश का चार्ज भी उसी के पास था। श्री सी० एच० पालन डम्पेकिटिंग आफिसर ने आकस्मिक निरीक्षण किया और भौतिक सत्यापन में 2700/-कैश कम पाया। बैंक की राशि का मिस एप्रोपियेशन, बैंक अभिलेख में काटफॉस और बैंक के हितों के विरुद्ध बेईमानीपूर्वक कुत्त आदि गंभीर आचरण करने में निपट पाया गया। यह भी उल्लेख किया है कि 4-3-86 को प्रार्थी ने लिखित में 3-3-86 को कैश बैलेन्स में लापरवाही से कमी होना के तथ्य का स्वीकार किया और एक प्रार्थनापत्र क्षमा याचना की भी पेश किया। प्रार्थी के कटाचरण के कारण 27-9-86 को निलम्बित किया गया। एवं निलम्बन आदेश के साथ प्रदर्श-3 भौतिक सत्यापन व जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदर्श-5 व आदेश प्रदर्श-6 दिया गया जो प्रार्थी को 29-9-86 को प्राप्त हुआ गया। यह उल्लेख किया है कि आंतरिक जांच प्रतिवेदन दिनांक 3-4-86 प्रदर्श-5 के आधार पर प्रार्थी के द्वारा कथित तलवाड़ा ब्रांच में कार्य के दौरान बैंक राशि के दुरुपयोग व भुविनिर्धोजन

य अधिवक्ता ने की गई अन्य गड़बड़ियों के लिये 18-11-86 को आरोपपत्र प्रदर्श-7 तथा गण्डीमेंट्री आरोपपत्र प्रदर्श-8 दिया एवं प्रार्थी ने 12-9-87 को जवाब में इन आरोपों को स्वीकार किया। इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि बैंक अधिकारियों ने आरोप स्वीकार करने के लिये प्रार्थी को किसी प्रकार का प्रलोभन आश्वासन दिया हो या मजबूर किया हो। प्रार्थी का स्वीकारोक्ति अभिकथन प्रदर्श आर-9 है। यह भी उल्लेख किया है कि 3-3-86 को हैड कैंशियर के रूप में प्रार्थी नियोजित था और एस० के० गुप्ता, लेखा-पाल थे। इबल लाक की चाबी के इन्चार्ज थे। 2700/- रुपये कौश में कम प्राप्ति के लिये 1350/- रुपये प्रार्थी एवं उनकी राशि श्री एस० के० गुप्ता से लेकर कौश में रख कर कमी को पूरा किया। यह भी उल्लेख किया है कि श्री एस० के० गुप्ता के बारे में क्या कार्यवाही की जाय इसके लिये प्रार्थी निर्देश नहीं दे सकता।

श्री जी० सी० चटर्जी, क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा श्री बी०के० कृष्णकुमार को उनके आदेश 18-11-88 में चार्ज कार्यवाही के लिये अधिकारी नियुक्त किया जिन्होंने 20-2-87 में जांच कार्यवाही प्रारंभ की एवं 21-10-87 को प्रार्थी को आरोपित आरोप में दोषी मानकर अभिनिर्णित किया। उनका प्रतिवेदन मक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जिन्होंने अपने आदेश 14-5-88 में प्रार्थी की सेवा से डिगमिस करने का आदेश पारित किया।

प्रार्थी ने 28-6-88 को डिप्टी जनरल मैनेजर के यहां अपील प्रस्तुत की जो 21-7-88 को समाप्त कर दी। विपक्षी का अभिकथन है कि प्रार्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरना गया। यह भी उल्लेख किया है कि प्रार्थी को गंभीर कदाचरण के आरोपों में सेवा से पृथक् किया गया है। अतः अब धारा 25 को छूटनी की परिभाषा में उसका कृत्य नहीं आता है। सारी जांच कार्यवाही द्विपक्षीय सेटलमेंट एवं न्यायिक सिद्धांत के अनुसार की गई है। अतः प्रार्थी की सेवामुक्ति के आदेश को न्यायोचित मानकर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण में दोनों पक्षकारण के प्रतिरक्षा के लिए अभिकथनों पर पूर्ण विचार करते हुए दिनांक 15-7-95 को विपक्षी द्वारा की गई जांच कार्यवाही को केयर मानी जाने का पृथक् से आदेश पारित किया गया।

प्रकरण में दोनों पक्षकारण की ओर से गंभीर रूप से केवलमात्र सेवा से पृथक् किये जाने के सजा के विन्द पर ही तर्क प्रस्तुत किये हैं।

विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी ने मेरे समक्ष गंभीर रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की सेवायें बैंक की हैं जहां पर कि सामान्य जन समुदाय के रोकड़ एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रलेख, जेवर आदि जमा रहते हैं। उनका तर्क है कि भौतिक सत्यापन में 2700/- की कय राशि पाई गई और प्रार्थी के द्वारा अपनी गलती की क्षमायाचना दी गई है। उनका तर्क है कि कथित आरोपों की निश्चिन्ता अनुसार जांच की गई है

और नियमों के तहत ही प्रार्थी को सेवा से पृथक् किये जाने का आदेश पारित किया है। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि जांच अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन को डिमिशनलरी ऑथोरिटी ने अवलोकन पर महामति व्यक्त की है और उसके उपरान्त की गई अपील में भी पृथक् अधिकारी द्वारा मस्तिक एप्लॉट करने के उपरान्त सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया। विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की सेवा में मैनेजमेंट का विश्वास हट जाने से और बैंक जैसी संस्था में कदाचरण के गंभीर आरोपों को मिट्ट पाये जाने पर सामान्यतया औद्योगिक अधि-करण को अब धारा 11(ए) के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में विनिर्णय 1993 (2) डब्ल्यू० एन० सी० 202 एवं 1995 एन० वाई. सी० 771 प्रस्तुत की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी को पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश देकर किसी प्रकार का प्रिमियम नहीं दिया जाना चाहिये। मैनेजमेंट के सेवा शर्तों के तहत लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। किसी भी प्रकार से अनफेयर नेबर प्रेक्टिस होने, विक्टिमाईजेशन किये जाने, नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांत को अवहेलना किये जाने, भेदभाव बरने जाने आदि के अभिकथन सिद्ध नहीं हैं। अतः प्रतिपादित सिद्धांत के तहत एवं तथ्यात्मक विवेचन व प्रलेखों के अनुरूप हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि किसी प्रकार का गबन किया जाना सिद्ध नहीं है। यदि वास्तव में प्रार्थी के द्वारा गबन किया गया होता हो उसकी फौजदारी कार्यवाही की गई होती। भौतिक सत्यापन में 2750/- रुपये कम पाये जाने पर तत्काल ही प्रार्थी ने 1350/- और 1350/- एस. के. गुप्ता, लेखापाल के द्वारा जमा कराये गये। विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि यदि वास्तव में कथित कम राशि के लिये प्रार्थी को दोषी माना जाता है तो कोई कारण नहीं है कि 1350/- रुपये जब श्री गुप्ता, लेखापाल ने भी जमा कराये तो उनके प्रति जांच कार्यवाही क्यों नहीं की गई है एवं उन्हें सेवा से पृथक् क्यों नहीं किया गया। अतः प्रथम दृष्टया ही मैनेजमेंट द्वारा भेदभाव बरना जाना स्पष्ट है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी प्रारम्भ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-कम-वाचमेन के पद पर तैनात हुआ और अच्छी सेवा के फलस्वरूप ही उसे पदोन्नति क्लेरीकल केडर में की गई। वास्तव में उसने अपने आरोपों को स्वीकार इसलिये किया कि उसे मैनेजमेंट के द्वारा यह आश्वासन दिया था कि इन वाक्यान्त को समाप्त कर दिया जावेगा। विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नति हुए कर्मचारी को ऐसा प्रेरित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कमजोर, असहाय और अधिक नहीं पढ़े किसी व्यक्ति से सहज समर्थ चतुर व्यक्तियों द्वारा ऐसा स्वाकांक्षित कथन लिखा लेना कोई असंभव नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि यदि वास्तव में मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया होता तो यह सामान्य परि-स्थितियों में नहीं माना जा सकता कि कोई व्यक्ति राशि की

कमी जैसे आरोपों जिसमें कि उसकी सेवा समाप्त होने का संशय हो सहज तरीके से स्वीकारोपित लिखाकर दे देगा। अतः विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिये कि मान्यता में मैनेजमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा लघु किस्म का दंड देकर ही इस घटनाक्रम को समाप्त कर देने के आश्वासन पर ही प्रार्थी के द्वारा ऐसा स्वीकारोपित कथन लिखाकर दिया गया था।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी तर्क है कि सभी साक्षीगण ने शपथपत्र पेश किये हैं और उसमें यह तथ्य उजागर हुआ है कि उन्हें मजबूरन गलत बयान देने के लिये प्रेरित किया गया था। विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि लेखापाल श्री एस. के. गुप्ता के समान दोषी होने पर भी उसके विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से भेदभाव बरते जाने का तथ्य पूर्ण प्रमाणित है। सभी अधिकारियों ने समान रूप से प्रार्थी को सेवा में भुक्त करने का मानस बनाया है उसका आधार यही है कि प्रार्थी के सही अभिकथनों पर गौर नहीं किया गया और एस. के. गुप्ता को बचाने का प्रयास किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की सोलह माल की लम्बी सेवा अवधि है और विपक्षी संस्थान ने विवादित आरोपपत्र के कृत्य के अतिरिक्त एक भी ऐसा ग़बन किये जाने के प्रलेख प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी का आचरण सामान्य रूप से भी कार्य निष्पादन में संतोषप्रद नहीं रहा हो। इसके विपरीत प्रार्थी ने मन् 72 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विपक्षी संस्थान में सेवा की और मन् 77 में उसे क्लर्क बनाया गया और लगभग उसने 10 वर्ष तक क्लर्क की सेवाएं संतोषप्रद दीं। अतः इन परिस्थितियों में यदि मैनेजमेन्ट को कथित दुराचरण के लिये दंडित करना भी था तो अन्य प्रकार से भी दंडित किया जा सकता था। न कि प्रार्थी एवं परिवार की जीविका के साधन को ही समाप्त कर देने के दण्ड से दण्डित करना ही केवलमात्र उपाय था। सामान्यतया कर्मचारी की सेवा की सुरक्षा का विधान है और दुराचरण के लिये मैनेजमेन्ट के द्वारा दण्डित किये जाने के लिये भी प्रावधान है, परन्तु सामान्यता सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इसी उद्देश्य से हस्व धारा 11(ए) के तहत औद्योगिक अधिकरण को यह शक्ति प्रदान की गई है कि ऐसे हार्ड केस में वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करे और सेवामुक्ति के आदेश को अनुचित माने। महज लोस आफ कोन्फीडेंस का तर्क अथवा प्रिमियम दिये जाने का तर्क भावनात्मक रूप से प्रभावी माना जा सकता है, परन्तु व्यवहारिक रूप में यह तथ्य परिस्थितियों में पृथक्-पृथक् प्रकरण में सिद्ध होना अनिवार्य है, क्योंकि सेवामुक्ति के प्रत्येक प्रकरण में यही तर्क मैनेजमेन्ट के द्वारा प्रस्तुत होता है तो इसका निष्कर्ष यह निकाला जाये कि हस्व धारा 11(ए) औद्योगिक अधिकरण किसी भी प्रकरण में सेवामुक्ति के आदेश को परिवर्तित करते में सक्षम नहीं है।

विद्वान् अधिवक्ता ने मेरे समक्ष विनिर्णय परमुराम मिश्रा बनाम यू. पी. स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन 1988 (56) एफ. एल. आर. पेज 289

2. राजस्थान कोपरेटिव स्पेनिंग मिल्स लि. बनाम राजेंद्र प्रसाद व अन्य 1987 (55) एफ. एल. आर. 558

3. जनार्दन रेड्डी बनाम डिपो मैनेजर ए. पी. एम. आर. टी. सी. हैदराबाद 1990 (61) एफ. एल. आर. 243

3. अरविन्द कुमार हीरा लाल मेहता बनाम बैंक आफ बड़ौदा 1992 (65) एफ. एल. आर. 1045

5. सी. नागराज भट्ट बनाम केनरा बैंक 1988 (57) एफ. एल. आर. 722

6. राम लाल खुगना बनाम स्टेट आफ पंजाब 1989 (59) एफ. एल. आर. 594

7. वर्कमैन भारत फिट वेस्टर प्रा. लि. बनाम भारत फिट वेस्टर प्रा. लि. 1990 (60) पेज 482

मैंने दोनों पक्षकारान के प्रस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यात्मक विषय एवं प्रलेखों का अवलोकन किया एवं हस्व धारा 11 (ए) की विधि व्याख्या पर प्रस्तुत दोनों पक्षकारान के द्वारा विनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं मेरे कार्यकाल के समय में इस विषय पर प्रस्तुत होने वाले विभिन्न विनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के तहत मेरे द्वारा निकाले गये निष्कर्ष निम्न हैं:

संशोधन से पूर्व की स्थिति यह थी कि सेवा समाप्ती की दण्डादेश के अधिकार मैनेजमेन्ट का होना माना गया था और केवलमात्र नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त की अवहेलना पाई जाने पर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस या विन्टे-माईज के तथ्य प्रमाणित पाये जाने पर एवं निकाले गए निष्कर्ष की वैधानिकता पाने पर ही सेवामुक्ति के दंडादेश में अधिकार के हस्तक्षेप को उचित माना गया था, परन्तु संशोधन के उपरान्त कर्मचारी की सेवा मुक्ति एवं सेवा से पृथक् किये जाने के आदेश में अधिकरण के हस्तक्षेप को विधि प्रावधानों के तहत बनाया गया है। यह अवश्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के विनिर्णयों में इसकी व्याख्या के तहत यह व्यवस्था की गई है कि सामान्यतया कदाचरण के सिद्ध आरोपों के ऐसे दंडादेश में अधिकरण को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जब तक कि निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण न हों अथवा आरोपित आरोप की तुलना में सेवामुक्ति को आदेश अनुचित प्रतीत न होता हो।

विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी ने जो तर्क एवं विनिर्णय प्रस्तुत किये हैं उनके तहत अधिकरण के हस्तक्षेप को उन परिस्थितियों में अनुचित पाया है जहां पर कि रोडवेज के



कर्मचारी कण्डक्टर के न केवल आरोपित आरोप को ही मिट्टा पाया है वरन् पूर्व में भी उसका ऐसा आचरण होने का साक्ष्य उपलब्ध था और ऐसे आधार पर मैनेजमेंट के कोन्फीडेंस समाप्त हो जाने से तथा ऐसे निरन्तर मिसकण्डक्ट में विपन्न रहने वाले कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश को प्रिमियम दिये जाने के समान माने जाने से प्रतिकर के हस्तक्षेप को अनुचित माना है। इन विनिर्णयों में भी पृथक-पृथक प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार अधिकरण के हस्तक्षेप किये जाने की वैधानिक शक्ति का अस्वीकार नहीं किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता ने इस विषय पर जो विनिर्णय प्रस्तुत किये हैं उन सभी में अधिकरण के हस्तक्षेप को अपायक व उचित माना गया है।

विवेचन का अभिप्राय यह है कि इस धारा 11 (ए) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिये अधिकरण का यह वैधानिक दायित्व है कि पृथक-पृथक प्रकरण की पृथक-पृथक परिस्थितियों का गंभीरता से अवलोकन करे, उन पर विचार करे।

प्रस्तुत प्रकरण में यह अवश्य विवाद रहित है कि प्रार्थी बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कम बाचमैन के रूप में सन् 1972 को बैंक में नियोजन में आया और उसकी सेवा से संतुष्ट होकर ही मैनेजमेंट ने सन् 1977 में उसे पदोन्नत क्लर्क के डर में किया और क्लर्क के पद पर पदस्थापित किया। कथित कदाचरण से पूर्व अर्थात् क्लर्क के रूप में प्रार्थी के द्वारा की गई दस वर्ष की सेवा अवधि में उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कदाचरण किया जाने अथवा अनुशासन भंग किये जाने अथवा कर्मस्थल में शिथिलता बरती जाने की कोई शिकायत हो ऐसा मैनेजमेंट का न तो मौखिक कथन है और न ही कोई प्रलेख पेश किया है। मौखिक सत्यापन के समय 2750/- की कमी पाई जाने के लिये जो कदाचरण का आरोप है उसमें भी 1350/- रुपये प्रार्थी ने तत्काल जमा कराये हैं और 1350/- लेखापाल एस. के. गुप्ता ने जमा कराये हैं। मैनेजमेंट के द्वारा समान कृत्य के लिये एस. के. गुप्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा प्रलेख पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने न केवल राशि जमा कराई है, वरन् कृत्य के लिये क्षमायाचना भी की है। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों को मैं स्वीकार करता हूँ कि संभव है कि प्रार्थी को ऐसी स्वीकारावृत्ति कथन करने के लिये तत्कालीन उच्च अधिकारी द्वारा प्रेरित किया हो कि उसे लघु दंड से ही दंडित किया जायेगा। अतः वो अपना आरोप स्वीकार करने। विभागीय जांच के दौरान साक्षीगण के दिये गये शपथपत्र को जिसमें उन्होंने प्रार्थी के विरुद्ध जबरन शहाबत देने के लिये प्रेरित करने का उल्लेख किया है, तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मैनेजमेंट के द्वारा इस कदाचरण के आरोप की कोई प्राथमिक इतला वर्ज नहीं कराई गई।

उक्त विवेचन के आधार पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि निकाले गये निष्कर्ष आरोप सिद्धी को मेरे समक्ष गंभीर

रूप से विवादित नहीं किया गया है। अतः मैं ऐसा कोई मत व्यक्त नहीं करता कि आरोप सिद्धी का निष्कर्ष सही नहीं माना जाये, परन्तु यह अवश्य विचारणीय है कि एक कर्मचारी जिसको कि सन् 72 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियोजन में रखा गया जिसकी सेवाएं संतोषप्रद पाने पर ही सन् 1977 में क्लर्क के डर में पदोन्नत किया गया, फिर दस वर्ष की सेवा अवधि में उसका कोई भी कृत्य विज्ञापितपूर्ण नहीं पाया गया एकाकी कृत्य 2750/- कम राशि जिसमें 1350/- अन्य कर्मचारी लेखापाल द्वारा भी जमा कराई गई और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, तथा प्रार्थी द्वारा किये गये कृत्य के लिये निष्पक्ष में माफी मांगी गई जो कथित आरोपी के ये एक साथ ही उसकी पूर्व की 16 वर्ष की गई सेवा को अनदेखा कर तौकरी से पृथक् कर देना एकानोभिक डेय के दंड से दंडित कर देना माना जायेगा विधि के अनुसार अन्य दंडादेश भी उपलब्ध है और मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रकरण की परिस्थिति में उन्हें पारित किया जाना कथित अपराध के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता। मेरे मत से वर्तमान में ऐसा कि रोजगार एक समस्या है, और कर्मचारी जिसने कि निष्पक्षी पायदान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सेवा काल प्रारम्भ किया है और 16 वर्ष की सेवाएं अलावा कथित आरोप के संतोषप्रद पाई गई हो वहां अन्य उपलब्ध दंडादेश को पर्याप्त नहीं मानकर सीधे ही सेवा से पृथक् कर देने के दंडादेश को उचित नहीं माना जा सकता और अब धारा 11(ए) के तहत अधिकरण के हस्तक्षेप को मैं अनिवार्य मानता हूँ। मेरे मत से प्रार्थी को अन्य प्रकार से दंडित किया जा सकता है और उसे जीवन में किये गये एकाकी गलती को सुधार कर अपने आचरण को मैनेजमेंट की आकांक्षाओं के और निर्देश के अनुकूल ढालने में सक्षम बनाये जाने के लिये एक अवसर दिया जाना उचित माना जा सकता है।

मैं प्रकरण की परिस्थितियों में विपक्षी के प्रार्थी की सेवामुक्ति के पारित आदेश को अनुचित मान कर संशोधित करता हूँ और यह आदेश पारित करता हूँ कि प्रार्थी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संबंधी प्रभाव से रोक दी जाती हैं और आगामी तीन वर्ष के लिये वह किसी भी पदोन्नति के लिये पात्र नहीं समझा जायेगा और तीन वर्ष की लगातार मैनेजमेंट के अनुसार संतोषप्रद सेवा पाने पर आगामी पदोन्नति के लिये इस अवधि के बाद ही कंसीडर किया जायेगा। यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की सेवामुक्ति से पुनः सेवा में लिये जाने की अवधि तक की अवधि को पहले मिलने वाले अवकाशों से जिनमें पूर्ण वेतन अवकाश, छद्म वेतन अवकाश, एवं अन्य मिलने वाले अवकाशों से समायोजित किया जायेगा और शेष अवधि को अवैतनिक अवकाश की श्रेणी में 'नो बर्क नो पे' सिद्धांत के आधार पर मानी जायेगी। यह सेवा की अवधि सेवा की निरंतरता में आगामी सेवा शर्तों के लाभों के लिये आंकी जायेगी। प्रार्थी को मिल सकने वाली राशि का भुगतान विपक्षी तीन माह की अवधि में करेगा अन्यथा प्रार्थी को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा।

प्रार्थी को तुरन्त प्रभाव से सेवा में लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

प्रकरण के तथ्यों में दोनों पक्षकारान का सर्वा मुकदमा अपन-अपना वहन करेंगे।

पंचाट आज दिनांक 1-8-1995 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

ओ. पी. गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

का. आ. 2467.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूच में, केन्द्रीय सरकार केनारा बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुसूच में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, अल्लपुजा के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 16-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन--12012/270/91-आई. आर. (बी.-2)]

ब्रज मोहन, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1995

S.O. 2467.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Alappuzha as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 16-8-95.

[No. 1-12012/270,91-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, ALAPPUZHA

(Dated this the 24th day of July, 1995)

#### PRESENT :

Shri K Kanakachandran, Industrial Tribunal  
I.D. No. 5/72

#### BETWEEN :

The Deputy General Manager, Canara Bank, Circle  
Office, Trivandrum.

#### AND

The Workman of the above concern Sri A. K. Narayanan S/o. A. A. Kesavan, Gold Smith, P.O. Kanansserry, (via) Arivannoor-680102, Trichur District.

#### REPRESENTATIONS :

Sri Raju Abraham,  
Advocate, "Kalpaka",  
Ravipuram Road,  
Cochin-16.

For Management.

M/s. M. Ramachandran &  
A. Jayasankar,  
Advocates, Cochin-17.

For Workman.

#### AWARD

1. This industrial dispute was referred to this Tribunal by the Government of India under Sec. 10(2A)(1) of the Industrial Disputes Act. The schedule contained in the reference

order No. L-12012/270/91-IR(B.II) dated 7-2-1992 reads as follows :—

"Whether the action of the management of Canara Bank in terminating the services of Shri A. K. Narayanan, NND Agent and Jewel Appraiser, Guruvayoor Branch with effect from 7-10-1987 is justified? If not, to what relief Shri Narayanan is entitled?"

2. In the claim statement filed by the workman it is stated that he was appointed as a Gold Appraiser and NND Agent on the basis of orders given to him by the Canara Bank, Guruvayoor Branch. His appointment as a Gold Appraiser was by an order dated 10-1-1974. But his appointment as an NND Agent was by an order dated 15-9-1983. His services were terminated through a letter of the management Bank dated 7-10-1987. According to him the termination order was issued by raising certain allegations against him and in fact it was in violation of the principles of natural justice. According to him the attempt on the part of the management was to keep him out of employment and to deny him various benefits. At the time of termination neither notice nor any compensation was paid to him. Since he was having continuous service for more than 240 days, the termination in his case is illegal and in violation of Sec. 25, F, 25G and 25H of the I.D. Act. Since he was living solely on the income from his employment and no alternative employment was obtained so far, an award may be passed directing the management to reinstate him in service with benefit of backwages.

3. The management in their counter statement has repudiated the contentions of the workman. According to them he was engaged as a jewel appraiser as per the special contract dated 10-1-1974. His duty was to appraise the jewelries which would be brought by the customers of the Bank for pledging. He was also engaged as agent for three different deposit schemes viz., Nitya Nidhi Deposit Scheme, New Nayanidhi Deposit Scheme and Balashema Deposit Scheme through separate agreements dated 17-6-1974, 18-1-1983 and 15-9-1983. While he was functioning such an agent, he misappropriated certain amounts from the collections he made on 20-6-1987 and 11-9-1988 and tampered the pass book of the customers. Only because his action was found prejudicial to the interest of the Bank, the contract with him was terminated by a communication dated 7-10-1987. The workman was never worked as an employee in order to seek protection under the I.D. Act. He was only an independent contractor and Agent in terms of contractual agreement executed on different dates. As per the terms of the contract, the management Bank is entitled to to the interest of the Bank. The relationship between the workman and the Bank was only that of principal and agent and not that of employer and employee. As per the contract dated 10-1-1974 he was engaged as a jewel Appraiser on the basis of commission. Therefore there was no master and servant relationship. There was no supervision and control over the appraising work done by him. The primary duty of the workman was to weigh the ornaments brought in the Bank for pledging and to appraise the quality, purity and value of the gold. He work of appraisal was exclusively left to him as it is depending on his own technique and experience. The Bank introduced various kinds of deposits for encouraging the members of the public to open savings through Nityanidhi Accounts. As an agent, the workman herein had to go to the residence or place of business of the depositors for making daily or weekly collections. On the basis of collections so made, he would be given commission on pro rata basis. He was not given hire or reward so as to treat him as a workman as defined in Sec. 2(s) of the I.D. Act. He was not borne on the muster roll of the Bank. He was not admitted to the Provident Fund Account. Nor was he contributing to any Provident Fund. He was not obliged to adhere to any duration of work. He was not required to mark attendance and he was not paid any wages or salary. He was not under obligation to remain in the Bank during specified hours. He cannot be transferred from Branch to Branch. There is no prohibition against doing any work by him under any other person. The Bank had given recognition to several employees union and in none of those unions, he is a member. He is not required to possess any prescribed qualification in order to seek agency

in the Nityauidha Deposit Scheme. No appointment Order was issued to him. The All India settlement with the Bank Employees are not at all applicable to the agents like the workman herein. Moreover he can depute any person of his choice for making collection just like any other agents. Therefore, according to the management, in no manner the worker herein is entitled to seek any sort of benefit under the Industrial Disputes Act. Moreover the employees of the Canara Bank are governed by the Service Code issued from time to time. The worker will not come within the purview of any of the Service Code. In none of the categories mentioned in the Service Code, the agent like the workman would come. He cannot be treated as an employee of the Bank. There is no recruitment, probation, confirmation and promotion in respect of this agents. Therefore, according to the management, for no relief the workman herein is entitled.

4. From the pleadings of the parties herein and the evidence adduced it has come out that the workman was working both as a Jewel Appraiser and as Deposit Collector in one of the branches under the management Bank. Regarding the status of Jewel Appraiser employed by Commercial Bank there is a clear decision by the Supreme Court. In management of *M/s. Puri Urban Co-operative Bank v. Madhusudan and another* [IT 1992 (3) SC 290] the Supreme Court held as follows :—

“Prima facie test of relationship of master and servant is the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant (the measure of supervision and control apart) not only in the matter of directing what work the servant is to do but also the manner in which he shall do his work”.

Regarding the work of a Gold Appraiser it is observed that :—

“Now engaging Sahu was to require him to weigh the ornaments brought in the Bank for pledging and to appraise their quality, purity and value. He could be directed to do this but not the manner in which he shall do it. That was left to him exclusively, as it depended on his skill, technique and experience. Besides under the terms of engagement he was required to, and he did, execute a bond indemnifying and holding himself responsible to the Bank for all his acts and commissions as an appraiser, and be accountable for the loss sustained by the Bank on account of under-valuation of the gold pledged with it.....

These particulars, not by themselves, but in the totality of circumstance indicate lack of master and servant relationship”.

5. If the workman was doing only the work of a Jewel Appraiser he could not be considered as a ‘workman’ as defined in the I.D. Act and in that case no relief could be granted to him. But it is the admitted case by both sides that he was working as a Deposit Collector and rendering service to the management Bank, of course, in terms of the contractual agreement with the Bank. Depending upon the quantum of work done by him he was being paid commission. The question whether a person who is receiving more commission for the work rendered by him could be treated as a workman who is doing any kind of manual, skilled or unskilled, technical or operational or clerical work. The Supreme Court had occasion to deal identical matter in *State of Assam v. Kanak Chandra Dutta* (1968) 1 LLJ 288. It was held that remuneration could be by way of commission on collection also. It was further held that the post outside the regularly constituted service need not necessarily carry “a definite rate of pay” and it can be by way of a compensation or commission or collection of Government dues also.

6. The status of Pigmy Collectors who are standing on identical footing as that of Commission Agents was subject matter in several cases. In *Silver Jubilee Tailoring House v.*

Chief Inspec.or of Shop and Establishment, (AIR 1974 SC) the Supreme Court held :—

“The right to control the manner of work is not the exclusive test for determining the relationship of employer and employee and it is also to be considered as to who provides the equipment and tools and who has the right to reject the end product”.

7. In another case *Rajaram Rokela v. Shriram* (1977 Lab. IC page 1594) it was held that :—

“Piece rate paid Carpenters working under the supervision of the employer and work as per the specification and specific direction of employer are workmen”.

8. The Madras High Court in *management of Indian Banks Association v. Industrial Tribunal, Madras* and another (1990 1 LLJ 50) had occasion to decide the issue relating to the status of a Tiny Deposit Collectors. The Division Bench of the Madras High Court in the above case held that Tiny Deposit Collectors will come under the definition of workman and therefore they are entitled for the protection as envisaged in the I.D. Act.

9. Although there are several decisions in support of the case projected by the workman in this case there are certain other decision also in conflicting terms with the decisions referred above. While discussing the status of a person who is rendering some kind of service to the employer, the Supreme Court observed in *Shankar Balaji v. State of Maharashtra* (AIR 1962 SC 517) as follows :—

“The control of the management which is a necessary element of the relationship of master and servant is not directed towards providing or dictating the nature of the article to be produced or the work to be done, but refer to the other incidents having a bearing on the process of work the person carries out in the execution of the work. The manner of work is to be distinguished from the type of work to be performed.”

10. Yet another decision the Kerala High Court in *Mattancherry Mahajan Co-operative Bank v. P. B. Radhakrishna Pai and Others* held different view, of course, that was a decision rendered while interpreting the definition of ‘employee’ with reference to Shop and Commercial Establishments Act. It is doubtful whether the rationale laid down while interpreting the terms ‘wholly or principally employed’ has got any bearing with the definition of ‘workman’ as defined in the I.D. Act. If we relies on various decisions rendered by the Higher Courts it is very difficult to decide the issue in the right perspective. This Tribunal had occasion to consider identical issue in connection with the Pigmy Collectors working in the Syndicate Bank. It is useful to extract a few sentences from the award of this Tribunal in I.D. 17/92 which was published in the Official Gazette. In paragraph 7 of that award it was observed :

“7. Now let us see the nature of work to be done by the worker concerned. She had to collect deposits from the customers of the Bank regularly in accordance with the mutually agreed terms and conditions. She had to render true and correct account of the deposit collected. The deposit collected shall have to be accounted at the specified branch on the next working day itself. She had to use Bank Stationery for all work connected with deposit collection. She had to maintain the register regarding the collection which as to be duly verified by the Branch Manager or the authorised officer, therefore the position emerges is that in a different method of working arrangement, deposit collections are being made by the Bank. Instead of Customers directly coming to the Bank and making deposit, the Bank itself through their agents like Pigmy Deposit Collectors goes to the customers and receive deposits. No doubt, that is for and on behalf of the Bank. Such kind of arrangement itself is to attract customers and to achieve maximum deposit from the willing depositors. Therefore the nature of work which had been done by these agents is almost identical with the works which are performed by the official of the Bank. But the only difference is that

the deposits are accepted outside the premises of the Bank. In view of this arrangement for mobilising maximum deposit, the persons rendering service for such deposit mobilisation are also to be treated as part of the establishment. Only difference is that when regular staff are assured on regular hire or reward every month, this deposit collectors are entitled for remuneration only on the basis of the quantum of work done and the gain achieved out of that. Merely because they are not rendering service to the Bank in a systematic and regulated atmosphere, it cannot be said that they are not rendering service for hire or reward for work connected with the work of the establishment. Therefore I hold that this Adarsh Deposit Collectors will also come under the definition of 'workman' as defined in the I.D. Act. The learned counsel for the worker had brought to the notice of this Court a judgement of the Madras High Court in Management of Indian Bank v. Industrial Tribunal, Madras and another [1990] (1) LLJ 50]. In that case the issue raised was also identical. In stead of Adarsh Deposit Collector, the case of a Tiny Deposit Collector was subject to litigation. The Division Bench of the Madras High Court held that the Tiny Deposit Collector will come under the definition of 'workman' and therefore they are entitled for protection as envisaged in the I.D. Act. Since the facts are identical and terms and conditions for appointment are also similar, the rationale laid down by the Madras High Court can be safely applied in the case on hand also."

11. The award of this Tribunal in Syndicate Bank vs. Sasikala (I.D. 17/92) has not been reversed so far by the Higher Courts. In view of that the rationale adopted by this Court is equally applicable in this dispute also, because, the status of the workman concerned herein is identical as that of the workman concerned in I.D. 17/92 also.

12. In the result, an award is passed holding that the termination of service of the workman concerned who was a Nithyanidhi Deposit Collector is declared as illegal. He is entitled to continue in service of the Management Bank till his service is terminated in accordance with the provisions contained in the Industrial Disputes Act. During the period in which he was kept out of service, he shall be paid half the wages. The basis for determination of his monthly wages shall be the average of the remuneration or commission whatever it be he had been receiving during the period of one year immediately preceding the date of termination.

(Dated this the 24th day of July, 1995.)

K. KANAKACHANDRAN, Industrial Tribunal

#### APPENDIX

(I.D. NO. 5/92)

Witness examined on the side of the Management :—

MW1 : B. R. R. S. Iyer.

Witness examined on the side of the Workman :—

WW1 : A. K. Narayanan.

Exhibits marked on the side of the Management :—

M1 : Photocopy of the Contract Agreement dated 28-1-1974 between the Management and the workman.

M2 : Photocopy of the Contract agreement dated 17-6-1974 between management and workman.

M3 : Photocopy of the agreement dated 15-9-1983 in respect of the Scheme 'Balashema Nidhi'.

M4 : Photocopy of the agreement dated 18-11-1983 in respect of New 'Nithya Nidhi Deposit Scheme'.

M5 : Copy of the Letter dated 7-10-1987 of the Management issued to the Workman.

M6 : Manual of Institutions regarding Nithya Nidhi, Janapriya, Kiran and Balanidhi Deposits.

M7 : Service Code of Canara Bank Ltd.

Exhibits marked on the side of the Workman :—

W1 : Copy of the Appointment Order dated 31-5-1983 issued to the workman in respect of the 'Balashema Deposit Scheme'.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

का. अ. 2468.—श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मद्रास टेलीफोन, मद्रास के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट श्रीयोगिक विवाद में श्रीयोगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/98/91-आईआर (डीयू)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1995

S.O. 2468.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Madras as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Madras Telephones, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on 21-8-1995.

[No. L-40012/98/91-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU MADRAS

Monday, the 31st day of July, 1995

PRESENT:

Thiru N. Subramanian, B.A.B.L., Industrial Tribunal.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 73/91

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Management of Madras Telephones. Madras).

BETWEEN

Shri V. Raj,  
S/o S. Venkatesh,  
No. 5, Padavettamman Koil St.,  
1st Line, Chinthatheripat  
Madras-600002.

AND

The Chief General Manager,  
Madras Telephones,  
78, Purasawalkam High Road  
Madras-600010

REFERENCE:

Order No. L-40012/90/91-IR(DU), dated 7-11-1991, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference, claim and counter statements and other connected papers on record and both parties being absent, this Tribunal passed the following :

## AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

"Whether the termination of services of Shri V. Raj by the Management of Madras Telephones is justified? If not, to what relief he is entitled to?"

No representation for both. Both petitioner and respondent called absent, for the second time. Hence I.D. dismissed for default. No costs.

Dated, this the 31st day of July, 1995.

THIRU N. SUBRAMANIAN, Industrial Tribunal.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1995

का. प्रा. 2469.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बारको-गोवा के प्रबन्धतंत्र के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण पणजी-गोवा के पंचपट को प्रकाशित करनी है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/17/94-आई. आर. (डी. यु.)]  
के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1995

S.O. 2469.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Panaji-Goa as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom District Manager, Vasco-Goa and their workmen, which was received by the Central Government on 21-8-1995.

[No. L-40012/17/94-IR(DU)]  
K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL GOVERNMENT OF  
GOA AT PANAJI

(BEFORE SHRI AJIT J. AGNI, HON'BLE PRESIDING  
OFFICER)

Ref. No. IT/18/95

Shri Basu T. Lamani,  
Majorda—Goa. ... Workman/Party I  
V/s.

1. The Telecom District Manager,
  2. The Sub-Divisional Officer,  
Phones, Vasco-Goa. ... Employer/Party II  
Party I-Workman absent.
- Party II-Employer represented by Adv. Y. M. Bodhankar/  
Adv. S. Joshi.

PANAJI, Dated : 20-7-1995

## AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and Sub-Section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act 14, of 1947) the Central Government by its order dated 23-2-95 bearing No. L-40012/17/94-IR(DU) referred the following dispute for adjudication by this Tribunal.

"Whether the action of the Department of Telecom District Managed Panjib-Goa and Sub-Divisional Offi-

cer, Phones, Vasco-da-Gama, (Goa) in stopping from services to Shri Basu T. Lamani, ex-casual mazdoor w.e.f. 30-5-1989 is justified and proper? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On receipt of the reference a case was registered under No. IT/18/95 and Registered A/D notices were issued to the Parties requiring them to attend the hearing fixed on 12-5-95 at 10.30 a.m. Both the parties were duly served with the notice. On the date of hearing the Party I (For short, workman) remained absent and the Party II (For short 'Employer') was represented by Adv. Shri Shashikant Joshi. Since the workman was absent the case was adjourned to 12-6-95 for filing the statement of claim by the workman. However, on this date also, the workman remained absent and therefore final opportunity was given to the workman to file statement of claim on 10-7-1995. However, on this date also the workman remained absent and no statement of claim was filed on his behalf. Adv. Y. M. Bodhankar representing the Employer submitted that since it was the case of the workman that his services were illegally terminated by the Employer it was his duty to file the statement of claim in support of his contention. He submitted that the Employer did not desire to file any statement of claim on written statement and award be passed holding the action of the Employer in terminating the services of the workman as legal and justified.

3. The reference of the dispute has been made by the Central Government at the instance of the workman since he challenged the action of the Employer in stopping his services with effect from 30-5-1989 and as such he raised an industrial dispute. The Bombay High Court, Panaji bench in the case of V.N.S. Engg., & Services v/s. Industrial Tribunal, Goa Daman and Diu and another reported in FJR Vol. 71 at page 933 has held that there is nothing in the Industrial Disputes Act, 1947 that indicates a departure from the general rule that he who approaches a Court for a relief should prove his case i.e. the obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation, the test being that he who does not lead evidence must fail. Their Lordships of the Bombay High Court further held that the provisions of Rule 10-B of the Industrial Disputes (Central Rules 1957) which requires the party raising a dispute to file a statement of demands relating only to the issue in the order of reference for adjudication within 15 days from the receipt of the order of reference and forward copies to the Opposite party involved, clearly indicates that the party who raises the industrial dispute is bound to prove the contention raised by him an Industrial Tribunal or Labour Court would be erring in placing the burden of proof on the other party of the dispute. In another case, i.e. in the case of V. K. Raj Industrial v/s Labour Court (I) and others reported in 1981 (29) FLR 194, the Allahabad High Court has held that the proceedings before the Industrial Court are judicial in nature even though the Indian Evidence Act is not applicable to the proceedings before the Industrial Court, but the principles underlying the said Act are applicable. The High Court has further held that it is well settled that if a party challenges the validity of an order, the burden lies on him to prove the illegality of the order and if no evidence is produced the Party invoking the jurisdiction must fail. The High Court has also held that if the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the Government cannot be answered in favour of the workman and he will not be entitled to any relief. I am entirely in agreement with the said decision or the Allahabad High Court.

4. In the present case, since the dispute was raised by the workman and that it is at his instance that the reference was made by the Government the burden on the workman to prove that the action of the Employer in terminating his services w.e.f. 30-5-1989 was not proper and justified. However, the workman inspite of having been given several opportunities to file the statement of claim did not do so nor produced any evidence. In fact, the workman right from the first date of hearing did not participate in the proceedings. Therefore, there is no material before me to hold that the action of the Employer in terminating the services of the workman was not justified and proper. In the absence of evidence it cannot be held that the action of the Employer in terminating the services of the workman is illegal. In the circumstances, I hold that the workman has failed to

prove that the action of the Employer in stopping his services w.e.f. 30-5-1989 is not justified and proper and hence I pass the following order.

### ORDER

It is hereby held that the action of the Department of Telecom District Manager, Panajim-Goa and Sub-Divisional Officer, Phones, Vasco-da-Gama (Goa) in stopping the services of workman Shri Basu T. Lamani, ex-casual mazdoor with effect from 30-5-1989 is justified and proper.

No order as to costs. Inform the Central Government accordingly.

AJIT J. AGNI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1995

का. आ. 2470.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एल. आई. सी. आफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.—17012/17/92—आई. आर. बी.-2]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd August, 1995

S.O. 2470.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workmen which was received by the Central Government on 21-8-1995.

[No. L-17012/17/92-IR (B-II)]  
BRAJ MOHAN, Desk Officer

### AN NEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU  
MADRAS

Tuesday, the 1st day of August, 1995

PRESENT :

Thiru N. Subramaniam, B.A.B.L., Industrial Tribunal.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 66/1992

(In the matter of reference for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of LIC of India, Madras.)

### BETWEEN

Shri P. Jayakumar,  
No. 16, Pugalendi Keolaprubakkam,  
Villupuram,  
South Arcot Dist.

### AND

The Senior Divisional Manager,  
LIC of India,  
Madras Division,  
Madras—600002.

REFERENCE :

Order No. L-17012/17/92-IR(D.II), dated 30-7-92,

Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.  
This dispute coming on this day for final disposal in the

presence of Thiru S. Masilamani Advocate appearing for the Management, upon perusing the reference, claim and counter statements and other connected papers on record and the Workmen being absent, this Tribunal passed the following

### AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the Management of LIC of India, in terminating the services of Shri Jayakumar, Apprentice Development Officer w.e.f. 2-7-85 vide order dated 10-9-85, is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

Petitioner not present. Petitioner did not appear from August, 1994. Today also petitioner not present. Hence I.D. is dismissed for default. No costs.

Dated, this the 1st day of August, 1995.

THIRU N. SUBRAMANIAN, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1995

का. आ. 2471.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार देना बैंक के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.—12012/16/91-आई. आर. बी.-2]

पी. जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd August, 1995

S.O. 2471.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 21-8-95.

[No. L-12012/16/91-IR(B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-2/36 OF 1991

Employers in relation to the management of Dena Bank

### AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employer : Shri S. K. Talsania, Advocate.

For the workmen : Shri B. W. Vaidya, Advocate.

Bombay, dated 1st August, 1995

### AWARD

The Government of India Ministry of Labour by its letter No. L-12012/10/91-IRB-2 dt. 24th June 1991 had referred the following industrial dispute for adjudication.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dena Bank in relation to its Navi Peth Branch, Solapur, in not allotting the allowance carrying post the Head Cashier category 'E' to Sh. Asawa w.e.f. 1-2-1979 keeping in view of the settlement signed between the employer and All India Dena Bank Employees Co-ordination committee on 7-4-1978 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. Yadav the General Secretary of the Bank Employees Union, Solapur filed a statement of claim for the worker J.B. Asawa. It is contended that Asawa was initially appointed as a Cashier-cum-clerk at Chati Gali Branch, Solapur of Dena Bank w.e.f. 12-4-1971. He was then subsequently transferred to Navi Peth. There he worked till 17-7-78. On 1-2-1979 the functioning of currency chest started at Navi Peth Branch Solapur. Asawa worked in that capacity also.

3. Later on the Bank by an administrative circular inter alia released of a cashier allowance to cashier working in currency chest.

4. The workmen contended that in view of the provisions of agreement dt. 29-9-1980 read with original agreement dt. 7-4-1978, he ought to have been posted incharge of currency chest. But he was not given the post which is illegal. He made several oral representation to the Bank. But it was of no use. He also wrote letters to the concern Officers but it met with the same fate.

5. On 14-3-1989 the Solapur Bank Employees Union Solapur addressed to the Assistant Labour, Pune and requested him to take the matter for Conciliation. The Bank filed its reply on 30-6-1989. Ultimately the Bank did not agree with the request of the Union. In result the Assistant Labour Commissioner (Central) submitted its failure report to the authorities on 12-10-1990.

5. The workman contended that in view of the agreements the post by the circular dt. 21-8-1980 should have been given to the workman. It is, therefore, submitted that it may be declare that the Bank was not justified in allotting such a post to the workmen with other reliefs which he is entitled to.

6. The management resisted the claim by their written statement (Ex. '4'). It is submitted that the dispute is not maintainable before the Tribunal and is liable to be rejected. It is aver that in view of the letter dt. 28th September, 1980 which was issued by the Bank the Head Cashier category 'E' was created and the claim of the allowance w.e.f. 1-2-1979 is devoid of any merit. It is pleaded that in view of the circular dt. 21-8-1980 the management decided norms of granting Head Cashier category 'E' allowance and advised the Branches and all concern about the same.

7. It is pleaded that the workman raised his claim for the first time in the year 1983 when the post was allotted to Mr. Deshpande. Hence the claim being bilated cannot be considered.

8. Thereafter again on 7-7-1987 he raised that claim. Thus on the ground of latches and wilful delay neglect the claim of the workman, deserved to be rejected. It is pleaded that if a cashier is assigned with work of handling cash in a currency chest, he will be sanctioned special allowance for head cashier category 'E' and not if he is not assigned such dual responsibilities and functions. Since Mr. Asawa was not assigned the duties of currency chest till 1-2-1989 while he was transferred on 17-7-1987 to Chaligate Branch. The question of payment of Head Cashier category 'E' allowance to him does not arise. Under such circumstances the claim is unjust. It is submitted that the interpretation which is tried to be made out by the Union in respect of the two agreements is incorrect. It is prayed that the claim of the workman deserved to be dismissed.

9. My Learned Predecessor framed issued at Ext. '5'. The issues and my findings thereon are as follows :

Issues	Findings
1. Whether this Central Government Industrial Tribunal No. 2 Bombay has jurisdiction to entertain and decide the present reference?	Yes.

2. Whether the prayer of the workman in the present Reference must be rejected on the alleged ground of latches, willfull delay and negligence on the part of the workman?

Yes.

3. Whether the action of the management of Dena Bank in relation to its Navi Peth Branch, Solapur in not allotting the allowance carrying post of the Head cashier category 'E' to Shri Asawa w.e.f. 1-2-1979 keeping in view of the settlement signed between the employer and All India Dena Bank Employees Co-ordination Committee on 7-4-78, is justified?

Does not survive, if survives not justified.

4. If not, what relief the workman is entitled to?

Does not survive, if survives entitled to the cashier category 'E' allowance from 1-7-80 to 31-3-1994.

5. What Award

As per the order.

## REASONS

10. In the written statement the contention is taken that the Tribunal has no jurisdiction. It is not supported with any argument. The reference relates to the service condition of the Award staff. It has jurisdiction to decide it.

11. It is not in dispute by the wordings of the reference, the workman claims the special allowance from the creation of the post of cashier category 'E' that is from 1-7-1980 till the post was given to him on 31st of March, 1994. It is tried to argue on behalf of the management that the claim has to be rejected on the basis of latches. I am inclined to accept this submission. It is because Mr. Deshpande was given special allowance of cashier category 'E' from 1-7-1980. The workman wrote a letter to the branch manager Dena Bank for the first time on 5th of July, 1983. In the said letter he had mentioned that even he is entitled to the post of cashier category 'E' he was not given the same and he should be given the same. It appears that no action was taken on the basis of this letter. Admittedly the workman had not approached the Union nor any authorities to redress his grievance. Later on that is after about 4 years, on 7th of July 1987 he wrote another letter to the Regional Manager, Dena Bank, Pune. By this letter the workman again tried to raise his claim of cashier category 'E' from 1st of July 1980. But the main grievance appears to be of his transfer. Again the workman sit idle for some years. On 14-3-1989 the General Secretary wrote a letter to Assistant Labour Commissioner and brought to his notice the claim of the workman. In other words after about 9 to 10 years the workman in clear terms raised his demand. It has to be said it suffers from latches. As this is so he is not entitled to the relief which he has claimed.

12. Presuming that my findings on the above said issue is not correct I proceed to answer the remaining issues. It is not in dispute that an agreement was reached between the Bank and the Union in respect of special allowance on 7-4-1978. The relevant paragraphs are as follows :

1(b) Centre-wise seniority shall be on the basis of date of joining the service of the Bank in the clerical cadre. For those who are promoted from subordinate staff to clerical cadre, their seniority shall be reckoned from the date of promotion to clerical cadre. If more than one employees joined service or were promoted to the cadre on the same date and there is a tie, the employee who is senior in age will be considered senior. For the purpose of granting special allowance of a Head Cashier, an employee who has worked for the longest period in the

cash department will be considered to be senior, irrespective of whether the concerned employee is posted in the cash department or not at the time when the vacancy arises.

4. Employee on request transfer : An employee who has been transferred to another centre within the same region or another region at his own request, shall not be eligible for the allowance carrying post for a period of one year from the date of his reporting at the transferee branch region, even though he may be otherwise eligible for the post.

5. Filling up of the post and refusal to accept posting :

(a) Vacancy arising at any centre will be offered to the senior-most employee eligible to the post in terms of these norms and guidelines. On his refusal to accept the post, it will be offered to the next senior eligible employee. The employee refusing to work in allowance post will be debarred from working in allowance post for a period of three years.

(b) In case of newly opened branch, the Regional Manager/Personnel Manager will invite applications from the eligible employee and the senior-most eligible employee amongst the applicants will be offered the post. In case nobody applies for the post, the Regional Manager/Personnel Manager will have the discretion to post any suitable employee.

(c) Sweepers/Cleaners and Watch & Ward staff shall not be eligible for the post of daftry/hundi presenter. Peon-cum-Cleaner and Peon-cum-Watchman or vice-versa will, however, be eligible for the posts of daftry hundi Presenter.

(h) The agreement dated 7-4-1978 was reached by mutual agreement, by an agreement dated 20-9-1980.

13. By circular dt. 21-8-1980 (Ex. '3/5') the Bank reference to cashier allowance to cashier working in currency chest. The said circular inter alia reads:

"Re : Release of Cashier's allowance to Cashiers working in currency/chests.

It has been decided that if a cashier is assigned with the work of handling cash in the currency chests and is also holding two keys, he will be sanctioned special allowance for Head Cashier-category 'E' as specified in the Bipartite Settlement. The present quantum of allowance specified in the Bipartite Settlement for this category is Rs. 264/- p.m. and of which the amount ranking for provident fund is Rs. 161/-.

If, however, an officer is assigned to handle the work of currency chest, no cashier allowance will be payable to the employees in the Clerical cadre.

This allowance will be released from 1st July, 1980 only to those Cashiers who are handling the cash in currency chests and are holding the keys."

14. It is not in dispute that Mr. N. T. Deshpande is and was a clerk Junior to workman both at Solapur centre and the Region. On the basis of the above referred agreements, the post should have been given to the workman. The argument that at the relevant time the workman was not working there is without any base. Looking to the agreements which have referred above, even though he was not at Navi Peth at that time he should have been posted there.

15. It is tried to argue that the Union should accept the circular dt. 21-8-1980 as a whole and not in parts. In other words it is tried to argue that a post of category 'E' was created by the said circular with some qualification. The qualifications mentioned for getting such allowance in the said letter cannot be accepted as they are contrary to the agreements reached between Union and the Bank. After creation of the post the post should be given to the eligible employees on the basis of the agreements which I have referred above.

16. It is tried to argue on behalf of the management that Mr. Deshpande is a necessary party to the present reference. As he is not party no decision can be given. This cannot be accepted. What is to be seen in the said reference that whether the workman is entitled to the special allowance or not?

It is tried to argue that unless a person works he is not entitled to special allowance. As the workman had not worked, special allowance cannot be given to him. The applicant also is not acceptable because it is not that the workman was not ready to work in that capacity. His representations clearly speaks that he was and is ready and willing to work in that capacity. I therefore find no merit in the said submissions. For all these reasons I find that the action of the management is not justifying in denying the claim of the workman for the said post and the special allowance but as I have come to the conclusion that the action of the workman suffers from latches and delay, he is not entitled to the relief. I record my findings on the points accordingly and pass the following order.

#### ORDER

1. The action of the management of Dena Bank in relation to its Navi Peth Branch, Solapur in not allowing the allowance carrying post the Head cashier category 'E' to Shri Asawa w.e.f. 1-2-79 keeping in view of the Settlement signed between the employer and the All India Dena Bank Employees Co-ordination Committee on 7-4-78 is not justified.
2. As the claim suffers from latches and delay the workman is not entitled to any relief.
3. No order as to cost.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1995

का. आ. 2472—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसर्ग में, केन्द्रीय सरकार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सी. पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबन्धतल के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अतिकरण, बीकानेर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42012/104/92-आई. आर. (डी. डू)]

के. वी. डी. उन्नी, ईन्क अधिकारी

New Delhi, the 24th August, 1995

S.O. 2472.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bikaner as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Executive Engineer, CPWD and their workmen, which was received by the Central Government on 24-8-95.

[No. L-42012/104/92-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर

नं. मू. सी. आई. टी. सं. 1 सन् 1993

श्री किशनलाल पुत्र श्री भैरूदान ओजा गर्वनमेन्ट प्रेम के पीछे हनुमान हत्या, बीकानेर

—अपार्थी/अधिकारी

नाम

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेट्रन डिभिजन, सी. पी. डब्ल्यू.

डी., बीकानेर

—अपार्थी/नियोजक



रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 10(1) (घ), औद्योग. वि. अधिनियम,  
1947

न्यायाधीश—श्री ज्ञान प्रकाश पांडे, आर. एच. जे. एस.  
उपस्थिति—

1. श्री रूपराज तंवर, श्रमिक प्रतिनिधि

2. श्री मदनलाल श्रीमाली, नियोजक प्रतिनिधि

अधिनिर्णय दिनांक 6 जुलाई, 1995

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे अब के पश्चात् सिर्फ “अधिनियम” कहकर सम्बोधित किया गया है कि धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन भारत सरकार—श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं. एफ. 42012/104/92 दिनांक 20-9-93 द्वारा प्रेषित इस निर्देश के अन्तर्गत निम्न विवाद अभिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण में पठाया था।

“Whether the action of the Executive Engineer, Central Division, C.P.W.D., Bikaner in terminating the services of Shri Kishanlal S/o Shri Bherudan, daily wage Beldar, w.e.f. 1-7-86 is legal and justified? If not, what relief he is entitled to?”

2. प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र श्री भैरूदान जिसे अब के पश्चात् सिर्फ “श्रमिक” कहकर सम्बोधित किया गया है, की ओर से प्रस्तुत क्लेम विवरण के अनुसार इस प्रकरण के संक्षिप्त सत्य इस प्रकार है कि वह दिनांक 11-9-85 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बेलदार (चौकीदार स्टोर) के पद पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी. डब्ल्यू. डी.) बीकानेर में नियुक्त हुआ और एक कलेंडर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने के आधार पर लगातार कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया जिसकी सेवा दिनांक 30-9-86 को सहायक अभियन्ता एवं अधिसाणी अभियन्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बीकानेर द्वारा मौखिक रूप से बतौर छंटनी समाप्त कर दी।

3. श्रमिक का यह अभिवचन है कि सेवा समाप्त करने से पूर्व नोटिस अथवा नोटिस वेतन नहीं दिया गया, छंटनी मुआवजा नहीं दिया और न भारत सरकार से छंटनी की स्वीकृति ली गई और ना ही उस जैसे अन्य कर्मचारियों की बरिष्ठता सूच घोषित की गई जिससे “पहले आये पीछे जाये”, के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। श्रमिक ने इस सेवामुक्ति को अकारण, अनुचित बताते हुए अधिनियम की धारा 25-एफ, 25-जी, 25-एन, एवं नियम 77 के उल्लंघन में छंटनी करने का पक्ष रखते हुए यह भी कहा है कि उसने इस बाबत बार-बार नियोजक से सेवा में पुनः बहाल करने हेतु आपसी बातचीत की परन्तु नियोजक पक्ष द्वारा कोई गौर नहीं किया गया और वह आज तक बेरोजगार है। श्रम विभाग के माध्यम से औद्योगिक विवाद चलाने पर असफल वार्ता प्रतिवेदन के आधार पर यह रैफरेन्स इस न्यायालय में अधिनिर्णयार्थ आया है जिसके अन्तर्गत श्रमिक ने सेवामुक्ति आदेश दिनांक 30-9-86 निरस्त करने व पूर्ववत पद पर पुनः बहाल होने और बीच की अवधि का पूरा वेतन भत्ता दिलाने की प्रार्थना की गई है।

4. अप्रार्थीगण—मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी. डब्ल्यू. डी.) नोर्थ जोन, इस्ट ब्लॉक, आर.के.

पुरम, नई दिल्ली, अधिसाणी अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी. डब्ल्यू. डी.) सी-12 सादुलगंज, बीकानेर एवं सहायक अभियन्ता, केन्द्रीय उपखंड बीकानेर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी. डब्ल्यू. डी.) सी-12 सादुलगंज बीकानेर की ओर से प्रस्तुत उक्त क्लेम में श्रमिक को कैंज्युअल लेबर के रूप में दैनिक वेतन भोगी अर्थात् के कार्य के लिये रखता स्वीकार किया है और अन्य सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि किसी पॉइंट पर उसकी नियमित भर्ती नहीं की गई थी, श्रमिक ने स्वयं ही अपने इच्छा से काम पर आना बन्द कर दिया था और यह सेवा टर्मिनेट करने का मामला नहीं है बल्कि श्रमिक का सेवा में एम्प्लोयेमेंट होने का मामला है, श्रमिक कनिष्ठतम कर्मचारी था। नियोजक का अभिवचन है कि इस मामले में अधिनियम की धारा 25-एफ, 25-जी, व 25-एन, एवं नियम 77 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा वह अन्यत्र सेवा में धन अर्जित करता रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष कथन के रूप में यह भी कहा है कि जिस समय श्रमिक ने सेवा में आना बन्द किया उस समय वह वाटरमैन का कार्य किया करता था अब उस कार्य के लिये श्रमिक की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वाटरमैन की आवश्यकता तीन महीनों के लिये ही होती है, श्रमिक पिछला वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि जो भी विलम्ब किया गया है वह श्रमिक ने किया है और सेवा छोड़ने के बाद वह अन्य श्रोत से अब तक धन अर्जित करता रहा है। अतः श्रमिक का यह क्लेम सव्यव खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. श्रमिक ने अपने क्लेम के समर्थन में अपने स्वयं का शपथपत्र पेश किया है जिससे नियोजक प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई है इसके विपरीत नियोजक की ओर से सर्वश्री आई.एम. गुप्ता व एम.एल. रस्तोगी के शपथपत्र पेश हुए हैं जिनसे श्रमिक प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई है। प्रलेखाप साक्ष्य में श्रमिक की ओर से प्रदर्श डब्ल्यू-1 लगायत 11 दस्तावेजात की चित्र प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं जबकि नियोजक की ओर से दस्तावेजात प्रदर्श एम-1 लगायत 7 की चित्र प्रतिलिपियां पेश हुई हैं।

6. अंत में हमारे द्वारा विद्वान प्रतिनिधिगण उभयपक्ष को सविस्तार ध्यानपूर्वक सुना गया और प्रलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विधिममत्त विश्लेषण के आधार पर इस विवाद के सन्दर्भ में हमारा विधिममत्त निर्णय निम्न प्रकार है।

7. प्रलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विवेचन करने से पूर्व सर्वप्रथम हम विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा उठाई गई इस कानूनी आपत्ति पर विचार करना चाहेंगे कि रैफरेन्स में सेवामुक्ति दिनांक 1-7-86 अंकित है परन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में पत्रकारों द्वारा सेवामुक्ति का दिनांक 30-9-86 बनाया गया है—विद्वान प्रतिनिधि नियोजक के अनुसार सक्षम सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना में संशोधन के अभाव में श्रमिक द्वारा प्रस्तुत यह क्लेम चलने योग्य नहीं है इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक का तर्क था कि

वृत्तिवर्ण ही सेवानियुक्ति का दिनांक 1-7-86 उत्तम अधि-सूचना में अंकित हुआ है, वास्तविक सेवामुक्ति दिनांक 30-9-86 ही है और यही दिनांक श्रमिक अपने क्लेम विवरण में अंकित करके आया है यही नहीं जिस प्रसफल वार्ता प्रतिवेदन के फलस्वरूप यह विवाद प्रविनिर्णायक न्यायालय को पठाया गया है जिसकी प्रतिलिपि प्रलेख पर उपलब्ध है में भी यही दिनांक अंकित है और यह वृत्ति साधारण लिपिकीय वृत्ति है जिसे न्यायालय स्वयं सुधार करने में सक्षम है—फिर भी उनकी ओर से भारत सरकार से निवेदन कर वांछित संशोधनों के लिये प्रयास किये गये थे। बहस के दौरान ही उनकी ओर से एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह प्रकट किया गया है कि उनका भूमि सुधार हेतु कई प्रार्थनापत्र दिये हैं और एक पत्र यूनियन—रेलवे कैंजुबल लेबर यूनियन बीकानेर के महासचिव ने दिनांक 29-4-95 को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भी भेजा था परन्तु अब तक संशोधन नहीं हुआ है और न ही आज तक अस्वीकृत हुआ है अतः बिना संशोधन हुए भी न्यायालय स्वयं सेवामुक्ति दिनांक 30-9-86 मानकर निर्णय करने के लिये सक्षम है हमारी राय में पक्षकारों के बीच जब एक ही बार सेवामुक्ति होने का विवाद है और अमफन वार्ता प्रतिवेदन में भी सेवा मुक्ति का दिनांक 30-9-86 ही अंकित है तो रैफरेन्स में भूलवश सेवामुक्ति दिनांक 1-7-86 अंकित हो जाने को लिपिकीय भूल मानकर इस रैफरेन्स को उत्तरित किया जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है विशेषकर जबकि सक्षम सरकार द्वारा वांछित संशोधन को अब तक अस्वीकृत नहीं किया गया है। अतः विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा उठाई गई यह आपत्ति निरस्त की जाती है।

8. हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण के अन्तर्गत श्रमिक का अप्रार्थी के नियोजन में 240 दिन से अधिक सेवामुक्ति से पूर्व एक कलेंडर वर्ष में सेवारत रहना नियोजक द्वारा विवादित नहीं किया गया है अपितु स्वीकार किया गया है और नियोजक का स्पष्ट अभिवचन है कि यह श्रमिक स्वयं अपनी इच्छा से सेवा छोड़कर चला गया था और यह मामला छंटनी का नहीं होकर सेवा स्वयं श्रमिक द्वारा परित्याग कर देने का है इसलिये इस प्रकरण पर इस अधिनियम के प्रावधान धारा;—25एफ, 25-जी, 25-एन, एवं नियम 77 की पालना करने का अनिवार्यता नहीं थी और न ये प्रावधान लागू ही होते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के विधि सम्मत निस्तारण के लिये निम्न महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है :—

(1) दिनांक 30-9-86 से हुई श्रमिक की तथा कथित सेवामुक्ति इस अधिनियम की धारा 2(00) के अर्थ में छंटनी है ? और यह छंटनी इस अधिनियम की धारा 25-एफ, 25-जी, 25-एन, एवं नियम-77 की पालना किये बगैर अनुचित एवं विधिभ्रष्ट होने में निरस्तनीय है ?

(2) श्रमिक क्या राहत प्राप्त करने का अधिकारी है ?

9. प्रलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का प्रत्येक बिन्दु के संबंध में पृथक-पृथक विवेचन अब हम करना चाहेंगे, जो निम्न प्रकार है :

बिन्दु सं. 1

10. सर्वप्रथम, हम इस परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहेंगे कि आया श्रमिक की सेवामुक्ति इस अधिनियम की धारा 2(00) के अर्थ में छंटनी है अथवा नहीं ? इस संबंध में स्वयं श्रमिक ने तो अपने क्लेम की पुष्टि की और नियोजक द्वारा जिरह के दौरान की गई सुझावात्मक प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मैंने अपने आप नौकरी नहीं छोड़ी थी, मुझे एकमीशन श्री आई.एम. गुप्ता ने निकाला था, दिनांक 30-9-86 को निकाला था। पुनः जिरह में दिये गये सुझाव को अस्वीकार करते हुए स्पष्टतः कहा है कि यह कहना गलत है कि मैं काम को अपने आप छोड़कर चला गया था। इसके विपरीत नियोजक साक्षी श्री आई.एम. गुप्ता ने अपने शपथपत्र में शपथपूर्वक कथन किया है कि श्रमिक किशनचाल को दिनांक 11-9-85 को 13/ र. प्रतिदिन की दर से दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में मास्टररोल पर नियुक्ति दी गई थी जिसकी नियुक्ति का आदेश प्रदर्शन एम-1 है, उसका सशपथ कथन है कि श्रमिक ने मास्टररोल पर बेलदार के रूप में 17-6-86 तक कार्य किया था इसके बाद वह कार्य पर नहीं लौटा और उसने काम पर आने में स्वैच्छा से ना कर दिया था क्योंकि उससे खड़े खोदने और सीमेंट के धौले जिरह करने का कार्य उसकी इन हेल्थ के कारण नहीं हो पाता था तत्पश्चात् श्रमिक की प्रार्थना पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए और श्रमिक की इलहेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने अधीन वाटरमैन की सेवा के लिये नवीन नियुक्ति दे दी जो नियुक्ति आदेश प्रदर्शन एम-2 है, इस आदेश में 25-6-86 से 30-9-86 तक की अवधि का ही उल्लेख था इसके बाद कार्यालय में वाटरमैन की आवश्यकता नहीं थी और इसी कारण उनकी सेवा में वृद्धि नहीं की गई थी। नियोजक के इस साक्षी के अनुसार श्रमिक ने अपनी सम्पूर्ण सेवा दो यूनिटों में अलग-अलग की थी—प्रथम बार सहायक अभियन्ता की यूनिट में इसी साक्षी के अधीन 17-6-86 तक की थी और दूसरी बार अन्य यूनिट—अधिशासी अभियन्ता के अधीन 25-6-86 से 30-9-86 तक की थी, प्रथम यूनिट में श्रमिक ने 240 दिवस से ज्यादा सेवा एक वर्ष में निरन्तर की थी लेकिन 17-6-86 के बाद उसने स्वयं के अपनी इल हेल्थ के कारण काम पर आना बन्द कर दिया था और द्वितीय यूनिट में उस निश्चित अवधि की शर्त के साथ वाटरमैन की नियुक्ति प्राप्त की थी और निश्चित तिथि 30-9-86 के बाद विभाग को वाटरमैन की आवश्यकता नहीं थी इस कारण उनका कान्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया जाना संभव नहीं था और प्रेसिडिंग वर्ष में 240 दिन का कार्य नहीं किया था इसलिये मुआवजा व नोटिंग आदि देने की आवश्यकता नहीं थी, 1-7-86 को श्रमिक अधिशासी अभियन्ता के नियोजन में था और दिनांक 30-9-86 तक नियोजन में रहा था। नियोजक का यह साक्षी जिरह करने पर कहता है कि इसने मेरे अधीन 25-6-86 से 30-9-86

तक ही काम किया था—इसके पहले की मुझे रिकार्ड से ही जानकारी है। 17-6-86 को यह अपनी मर्जी से छोड़ गया था ऐसा प्रदर्श एम-4 में इसने दर्ज किया है, श्री एम.एल. रस्तोगी आईएन जिसके अधीन यह 17-6-86 से पहले काम करता था ने मुझे बताया था कि किशनलाल खुद छोड़कर गया है—प्रदर्श एम-7 द्वारा ऐसा लिखित में एम.एल. रस्तोगी ने मुझे दिया था, 17-6-86 से पहले की जानकारी मुझे रिकार्ड से ही है। 17-6-86 को खुद छोड़ गया इस बाबत प्रदर्श एम-4 तथा प्रदर्श एम-7 के अलावा और कोई रिकार्ड मेरे ज्ञान में नहीं है, 25-6-86 को नई नियुक्ति इसके जबानी कहने से प्रदर्श एम-2 द्वारा की थी तब इससे अर्जी नहीं ली शायद 30-9-86 के बाद हमारे पास काम नहीं था इसलिए समय नहीं बढ़ाया, सिनियरटी लिस्ट नहीं निकाली। नियोजक के दूसरे साक्षी एम.एल. रस्तोगी ने अपने शपथपत्र में यह कथन किया है कि 11-9-85 को प्रदर्श एम-1 द्वारा मस्टररोल पर दैनिक वेतन भागी श्रमिक के रूप में नियुक्त किया था जिसने बेजदार् श्रमिक के रूप में 17-6-86 तक कार्य किया और इसके बाद वह कार्य पर नहीं लौटा और उसने काश पर आने में स्वैच्छा में ना कर दिया। इस साक्षी ने नियोजक साक्षी श्री आई.एस. गुप्ता के शपथपत्र की पुष्टि करते हुए अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है और अपने कथन के समर्थन में प्रदर्श एम-1 लगायत 7 दस्तावेजात प्रदर्शित कराये हैं और जिरह करने पर नियोजक का यह साक्षी कहता है कि इसने स्वयं ही गड़्ढे खोदने का काम करने से मना कर दिया और जब मैंने कहा कि आप लेबर है आपको यह काम करना ही पड़ेगा तो उसने दूसरे दिन से काम पर आना बन्द कर दिया। यह कहता सही है कि श्रमिक जब दूसरे दिन काम पर नहीं आया तो हमने उसे काम पर आने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया, यह मुझे याद नहीं मैंने श्रमिक के काम पर ना आने बाबत एम.ई.एन. को लिखा है, यह कहता सही है कि हमारे पास किशनलाल का ठिकाना था। आगे जिरह में यह साक्षी खुद ही कहता है कि इस प्रकार उसने स्वयं ने ही मान लिया कि उसकी सेवा हमारे कार्यालय से समाप्त हो गई है। श्रमिक प्रतिनिधि द्वारा दिये गये हम सुझाव को गलत बताया है कि श्रमिक न गड़्ढे खोदने से मना नहीं किया हो।

11. प्रलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त प्रलेखीय साक्ष्य पर भी दृष्टिपात करना चाहेंगे, नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श एम-1 श्रमिक का नियुक्ति आदेश है जिसके द्वारा श्रमिक को प्रथमबार नियुक्ति दी गई थी और प्रदर्श एम-2 द्वारा श्रमिक को दुबारा 30-6-86 को प्रसारित इस आदेश के अन्तर्गत 25-6-86 से पानी की व्यवस्था करने हेतु 30-9-86 तक 13 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ही वाटरमैन की स्वीकृति दी गई थी, प्रदर्श एम-3 समझौता वार्ता के दौरान नियोजक द्वारा दिया गया लिखित प्रत्युत्तर है, प्रदर्श एम-4 श्रमिक द्वारा दिनांक 23-10-86 को लिखा गया सहायक इन्जीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बीकानेर के निमित्त प्रार्थनापत्र है जिस

पर उनके द्वारा जारी किया गया पत्र प्रदर्श एम-5 है, जिसमें आलेखित है कि “किशनलाल ओझा पुत्र श्री भैरुदान ओझा गवर्नमेंट प्रेस के पीछे हनुमान हत्था बीकानेर ने इस कार्यालय में दिनांक 11-9-85 से 17-6-86 तक कार्य किया है। तारीख 17-6-86 के बाद से इस कार्यालय में कार्यरत नहीं है। यह आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। यह प्रदर्श एम-5 पत्र सहायक इन्जीनियर का श्रमिक की प्रार्थना पर सहायक निदेशक उप श्रेणी नियोक्ता कार्यालय बीकानेर को लिखा गया है। प्रदर्श एम-6 सहायक श्रम आसक्त द्वारा प्रेषित असफल वार्ता प्रतिवेदन की चित्र प्रतिनिधि है, और प्रदर्श एम-7 नियोक्ता साक्षी एम.एल. रस्तोगी द्वारा ही अधिसूची अधिनियम को किया गया पत्र है। इसके विपरीत श्रमिक की ओर से प्रस्तुत बेजेज स्विप प्रदर्श डब्ल्यू-1 लगायत 10 है और प्रदर्श डब्ल्यू-11 अथवा वार्ता प्रतिदिन की ही चित्र प्रतिनिधि है। इसके अतिरिक्त और कोई साध्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

12. विद्वान् प्रतिनिधि नियोजक ने प्रलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं प्रदर्श एम-3, लगायत प्रदर्श एम-7 को आधार बनाते हुए तर्क रखा है कि श्रमिक स्वयं दिनांक 17-6-86 को सेवा छोड़कर चला गया था क्योंकि वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण खूबड़े खोदने व सीमेंट के थैलों की सिपिंग नहीं कर सकता था इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक का यह तर्क था कि हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण के अन्तर्गत एक बार स्वयं सेवा छोड़कर आने के उपरान्त पृथक युनिट के अधीन प्रदर्श एम-2 द्वारा दिनांक 25-6-86 में नयी नियुक्ति दी गई थी और इस युनिट में उसके द्वारा निश्चित अवधि 30-9-86 तक ही कार्य किया है जिसके बाद अप्रार्थी नियोजक के यह वाटरमैन की आवश्यकता नहीं होने के कारण सेवावधि आगे नहीं बढ़ाई जा सकी और उसकी यह सेवामुक्ति इस अधिनियम की धारा 2(00) के अन्तर्गत छंटनी नहीं है इसीलिये इस अधिनियम के आज्ञापक प्रावधान आकृष्ट ही नहीं होते हैं और न उनकी पालना नियोजक द्वारा करनी अपेक्षित थी। विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा किये गये इनके तर्कों के प्रत्युत्तर में बहस के दौरान विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक का यह तर्क था कि श्रमिक ने दो पृथक-पृथक युनिटों में भिन्न-भिन्न नियोजकों के यहां कार्य किया हो ऐसा तो नियोजक का अभिवचन ही नहीं है और अभिवचन के बिना जो साक्ष्य नियोजक की ओर से प्रस्तुत हुआ है, वह विश्वनीय नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार स्वयं नियोजक ने अपने प्रत्युत्तर में श्रमिक द्वारा 240 दिन से अधिक सेवावधि पूरी करना स्वीकार किया है और श्रमिक द्वारा अभिवचित नियुक्ति दिनांक 11-9-85 स्वीकार करते हुए नियोजक ने यह अभिवचन किया है कि श्रमिक ने स्वयं ही अपना इच्छा से काम पर आना बन्द कर दिया था उसे सहायक अभियन्ता एवं अभियाजी अभियन्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बीकानेर ने अपने मौखिक आदेश से सेवा पृथक करने का श्रमिक का यह कथन गलत है। यानि अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक की तथाकथित सेवामुक्ति दिनांक 30-9-86 को तो उनके द्वारा स्वीकार ही किया गया है—यह

बात दूसरी है कि श्रमिक को हटाया गया या वह स्वयं छोड़कर चला गया। विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक का यह भी तर्क था कि स्वयं नियोजक अपने प्रत्युत्तर में और साक्ष्य यह कहकर आया है कि जिस समय श्रमिक ने सेवा में आना बन्द किया उस समय वह वाटरमैन का कार्य किया करता था अब उस कार्य के लिये श्रमिक की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वाटरमैन की आवश्यकता तीन महीनों के लिये ही होती है। अब वाटरमैन की आवश्यकता नहीं है इस कारण सेवा के मामले पर विचार के समय इस तथ्य पर भी गौर किया जाना न्यायसंगत होगा—इसी आधार पर विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक का यह तर्क था कि प्रस्तुत प्रकरण के अन्तर्गत श्रमिक को हटाया जाना स्थापित है न कि उसके स्वयं के द्वारा भाग जाना प्रमाणित होता है।

13. प्रलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अति निकट बगहराई में अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी नियोजक इस श्रमिक द्वारा कार्य छोड़कर भाग जाने अथवा सेवा में परित्याग कर देने के तथ्य को भलीभाँति प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है—नियोजक का यह अभिवचन भी नहीं है कि श्रमिक ने भिन्न-भिन्न नियोजकों के यहाँ पृथक-पृथक यूनिटों में कार्य किया हो, प्रलेख पर उपलब्ध प्रदर्श एम-4 प्रार्थना पत्र में भी श्रमिक का स्वयं का कार्य छोड़कर चला जाना किसी प्रकार प्रमाणित नहीं है, अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि इस प्रार्थनापत्र के द्वारा श्रमिक ने नियोजन कार्यालय में अपना नाम जारी रखने के लिये नियोजक से कोई प्रमाणपत्र चाहा था और फिर प्रदर्श एम-7 पत्र जो कि सहायक अभियन्ता द्वारा लिखा जाना बताया गया है यदि उसमें तनिक भी सच्चाई होती तो अप्रार्थिगण ऐसा ही अभिवचन अपने उत्तर क्लेम में भी करते और स्वयं श्रमिक से सुझावात्मक प्रतिपरीक्षा भी करते। न तो नियोजक का ऐसा कोई अभिवचन है और न ही इस श्रमिक से इस प्रकार की कोई सुझावात्मक प्रतिपरीक्षा ही की गई है—इस प्रकार हमारी राय में नियोजक के साक्षीगण द्वारा इस सम्बन्ध में अपने-अपने शपथपत्रों में किये गये कथन पश्चात्पूर्व सोचो-सोचाएँ हुए कथन हैं जो विश्वसनीय नहीं हैं। श्रमिक का स्पष्ट कथन है कि उसे 30-9-86 को मौखिक आदेश से हटाया गया था और सेवामुक्ति से पूर्व 240 दिन से अधिक की सेवा अवधि पूरी करना स्वीकार किया गया है और उत्तर क्लेम में भिन्न-भिन्न यूनिट में कार्य करने बात भी श्रमिक से न तो प्रतिपरीक्षा की गई है और नहीं कोई अभिवचन ही नियोजक द्वारा किया गया है। जब श्रमिक स्वयं द्वारा कार्य छोड़कर चला जाना नियोजक प्रमाणित करने में असफल रहा है तो उसकी सेवामुक्ति साधारण सेवा मुक्ति है जो निश्चित ही इस अधिनियम की धारा 2(00) के किसी अपवाद में नहीं आने के कारण एक छंटनी है और इस छंटनी से पूर्व अधिनियम के इन आज्ञापक प्रावधानों की पालना में श्रमिक को एक माह का नोटिस अथवा नोटिस वेतन दिया जाने और निर्धारित फार्म पर सरकार की सूचना देने और बरिष्ठता सूचि प्रकाशित किये जाने का तो नियोजक का अभिवचन ही नहीं है अर्थात् श्रमिक की सेवामुक्ति जो छंटनी

है और यह छंटनी अधिनियम के इन आज्ञापक प्रावधानों यानि 25-एफ व नियम-77 की पालना नहीं की गई है और अब तक मुख्यस्थित विधि की स्थिति यही है कि इन आज्ञापक प्रावधानों का पालना किये बगैर हुई छंटनी अनुचित, विधि विरुद्ध एवं अप्रभावी होने से निरस्तनीय है और श्रमिक पुनः पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी है।

बिन्दु सं० 2

14. यह उल्लेख श्रमिक को दिलाई जाने वाली राहत से सम्बन्धित है, जैसा कि पर आलेखित किया जा चुका है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति “छंटनी” है और यह छंटनी अधिनियम की धारा 25-एफ, 25-जी एवं नियम-77 की पालना किये बगैर की गई है। फलस्वरूप ऐसी सेवामुक्ति अनुचित एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है और श्रमिक पुनः नियोजक की सेवा में पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि क्या श्रमिक सेवामुक्ति अवधि में पिछली समस्त बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण के अन्तर्गत दिनांक 30-9-86 से हुई सेवामुक्ति से सम्बन्धित यह विवाद भारत सरकार द्वारा सहायक श्रम आयुक्त की ओर से प्रेषित असफल वार्ता प्रतिवेदन दिनांक 15-6-92 प्रदर्श एम. 6/प्रदर्श डब्ल्यू. 11 के फलस्वरूप अधिनिर्णयार्थ पठाया गया है, इस असफल वार्ता प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भली प्रकार स्पष्ट है कि श्रमिक ने अपनी सेवामुक्ति से सम्बन्धित यह विवाद सर्वप्रथम 5-11-86 को समझौता कार्यवाही के लिये उठा दिया था परन्तु नियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में यह आया है कि समझौता कार्यवाही में भी श्रमिक अधिकतर अनुपस्थित रहा और विलम्ब उसी के कारण हुआ और इसी आधार पर विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की ओर से किये गये इस तर्क से सहमत है कि यह श्रमिक पिछला वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है श्रमिक द्वारा 5-11-86 को सर्वप्रथम विवाद प्रस्तुत करने के उपरान्त पक्षकारों के बीच समझौता अधिकारी के समक्ष कई बार बाताएँ हुई हैं दिनांक 12-2-87 को श्रमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण मामला बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार 1-9-86 द्वारा उठाये गये विवाद से सम्बन्धित कार्यवाही भी दिनांक 16-1-87 को श्रमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण बन्द कर दी गई थी तत्पश्चात् 30-8-90 को श्रमिक द्वारा पुनः विवाद उठाया गया है। इस प्रकार उनके अनुसार साक्षीगण के मौखिक कथन की पुष्टि प्रलेख पर उपलब्ध प्रदर्श एम-6/प्रदर्श डब्ल्यू-11 से भी होनी पायी जाती है कि श्रमिक के स्वयं के द्वारा समझौता कार्यवाही में विलम्ब किया गया है। अतः हमारी राय में भी इस श्रमिक को 30-8-90 से पूर्व की किसी अवधि के लिये कोई वेतन दिलाना उचित एवं वैध नहीं है। इस प्रकार सेवा मुक्ति दिनांक 30-9-86 से 30-8-90 तक की अवधि में श्रमिक कोई वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। श्रमिक सेवा मुक्ति के उपरान्त अन्यत्र कहीं लाभप्रद नियोजन में यह रहा हो, यह तथ्य प्रमाणित करने का भार

भी नियोजक पर है, नियोजक द्वारा अपने उत्तर क्रम में किये गये अभिवचन के समर्थन में साक्षीनेण ने शपथ कथन तो किया है परन्तु नियोजक साक्षी जिरह करने पर ही कहता है कि यह समझौता कर्ता में नहीं आया इसलिये कहता हूँ कि अन्यत्र कार्यरत होगा इसने धन एकत्र किया ऐसा मैंने सुनी सुनाई बात पर लिखा है जबकि श्रमिक का बयान जिरह में स्पष्ट कथन है कि नौकरी के बाद से आज तक मैं बरौजगार हूँ। प्रलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से नियोजक यह यह प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि श्रमिक सेवा मुक्ति के उपरान्त अन्यत्र लाभप्रद नियोजन में रहा हो। इन सब परिस्थितियों की दृष्टिगत रखते हुए हमारी राय में यह श्रमिक दिनांक 30-8-90 से सेवा में पुनः बहाल होने की बीच की अवधि का समस्त पिछला बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

15. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रेषित इस विवाद के सदर्भ में निम्न प्रकार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

- (1) श्रमिक किशनलाल पुत्र रुदान दैनिक वेतन भोगी बेलदार को दिनांक 30-9-86 से सेवा मुक्त करना उचित एवं वैध नहीं था परिणामस्वरूप वह अपने नियोजक अधिशाषी अभियन्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के नियोजन में पूर्ववत् पुनः पद व वेतन पर सेवा की निरन्तरता के लाभ के साथ नियोजित होने का अधिकारी है।
- (2) श्रमिक सेवा मुक्ति दिनांक 30-9-86 से 30-8-90 के बीच की अवधि में कोई वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है परन्तु 30-8-90 से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि का समस्त पिछला बकाया वेतन यह प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17(1) के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रकाशनार्थ पठाया जाये।

16. आज्ञा आज दिनांक 6-7-95 को सरे इजलास लिखाई व सुनाई जाकर हस्ताक्षरित की गई।

ज्ञान प्रकाश पांडे, न्यायाधीश

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1995

का.आ. 2473 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 14 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिनियर सुपरिन्टेण्डेंट पोस्ट ऑफिस, मथुरा के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/142/93-आई आर (डी यू)]  
के.वो.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th August, 1995

S.O. 2473.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Senior Suptd. Post Office, Mathura and their workmen, which was received by the Central Government on 25-8-95.

[No. L-40012/142/93-IR(DU)]  
K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 96 of 1994

In the matter of dispute between :

Sri Trilokchand,  
C/o Sri V. K. Gupta,  
2/363, Namnair,  
AGRA.  
AND  
Senior Superintendent,  
Post Office,  
MATHURA.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-40012/142/93-I.R. (D.U.) dated 14-11-94, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the action of the Senior Suptd. of Post Office Mathura in terminating the services of Shri Trilokchand, Postman, Aurangabad w.e.f. 25-9-91 is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?”

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He is not entitled to any relief.

3. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.आ. 2474. — भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के अधीन बनाए गए रेल कर्मचारी (नियोजन के घण्टे) नियम, 1961 के नियम 4 (2) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री आर.के.सैनी को उक्त नियम के तहत अपील सुनने के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में अधिमूर्चित करती है।

[फा.सं.एम.-66012/3/95 आई.एम.एम.-1]

(आर. के. रंगा, उपा, सचिव)

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2474.—In exercise of the powers conferred by Rule 4(2) of Railway Servants (Hours of Employment) Rules, 1961 under the Indian Railway Act, 1890 (9 of 1890) the Central Government hereby notifies Shri R. K. Saini, Joint Secretary in the Ministry of Labour as Appellate Authority to hear Appeals under the said Rules.

[File No. S-66012/3/95-ISH.I]

R. K. RANG, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.आ. 2475.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तारीख 16 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 172 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या-1, बम्बई के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक पद रिक्त हुआ है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री आर. एस. वर्मा को 9 अगस्त, 1995 से उक्त अधिकरण में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-11016/7/94-सी.एल.एस-II]

इन्द्र सिंह, अवर सचिव

## ORDER

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2375.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, No. 1, Bombay, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 172 dated the 16th January, 1960.

Now, therefore in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri R. S. Verma as the Presiding Officer of the said Tribunal with effect from 9th August, 1995.

[F. No. A-11016/7/94-CLS-II]

INDER SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.आ. 2476.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तारीख 22 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1698 द्वारा गठित श्रम न्यायालय संख्या 1, बम्बई के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक पद रिक्त हुआ है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री आर.एस. वर्मा को 9 अगस्त, 1995 से उक्त श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-11016/7/94-सी.एल.एस-II]

इन्द्र सिंह, अवर सचिव

## ORDER

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2476.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court, No. 1, Bombay constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 1698 dated the 22nd May, 1965;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri R. S. Verma as Presiding Officer of the said Labour Court with effect from 9th August, 1995.

[F. No. A-11016/7/94-CLS-II]

INDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1995

का.आ. 2477.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एल.आई.सी. आफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17012/20/94/आई.आर. (बी.-II)]

ब्रजमोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2477.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24th August, 1995.

[No. L-17012/20-94-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 56 of 1994

In the matter of dispute between :

The President,  
Lucknow Division Insurance Employees Association,  
C/o 269/104, Katra Neg Birhana,  
Lucknow.

AND

Senior Divisional Manager,  
Life Insurance Corporation of India,  
35/D, Rampur Bag,  
Civil Lines,  
Bareilly-243001.

## AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-17012/20/94-I.R.B-2, dated 30-6-94, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Bareilly in dismissing Shri Lalta Prasad Chourasia, Peon, from services w.e.f. 19-11-90 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled to?"

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.आ. 2478 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/36/93-आई.आर.बी.-2]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2478.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 24-8-95.

[No. L-12012/36/93-IR(B-II)]  
BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 56 of 1993

In the matter of dispute between:

Dy. General Secretary,  
U. P. Bank Employees Union,  
C/o Sri O. P. Mathur,  
117/K-36, Sarvodaya Nagar,  
Kanpur-208001.

AND

Regional Manager,  
Allahabad Bank,  
117/H-1/68-A,  
Pandu Nagar,  
Kanpur.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/36/93-IR. B-II, dated 30-7-93, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the claim of U.P. Bank Employees' Union that Sri Adit Narain Shukla, Clerk-cum-Cashier, is entitled to the benefit of annual increments which fell due on September 1986 and September 1987 is justified? If so, what relief is Sri Shukla entitled to?”

2. In spite of repeated opportunities, having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.आ. 2479.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/39/94-आई.आर.बी.-2]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2479.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24-8-95.

[No. L-12011/39/94-IR(B-II)]  
BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 20 of 1995

In the matter of dispute between.

Vice President,  
Union Bank Employees Association,  
C/o Union Bank of India,  
Civil Lines,  
Allahabad.

AND

Dy. General Manager,  
Union Bank of India,  
Sharda Tower,  
Kapoorthala,  
Aliganj,  
Lucknow.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12011/39/94-IR. B-2 dated 19-1-95, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the demand of the Union Bank Emp. Assn., U.P., Allahabad on the management of Union Bank of India, Lucknow that Shri Rajaram and Shri Satyanarain, part-time sweepers should have been granted full-time scale either prior to or from the date Shri Bhaggu Rawat, a junior part-time sweeper, was granted that scale i.e., 18-2-91 is justified? If so.

what relief are Shri Rajaram and Shri Satyanarain entitled to?"

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.ग्रा. 2480.—औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12011/48/94-आई.आर. (बी.-2)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2480.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24-8-95.

[No. L-12011/48/94-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 27 of 1995

In the matter of dispute between :

General Secretary,  
Union Bank of India Staff Association,  
UP-3/192, Viram Khand,  
Gomti Nagar,  
Lucknow.

AND

Dy. General Manager,  
Union Bank of India,  
Zonal Office, Sharda Tower, II Tal,  
Kapoorthala Complex,  
Aliganj,  
Lucknow.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12011/48/94-I.R. B-2 dated 20-2-95, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Union Bank of India, Lucknow in effecting recovery from the salaries of Shri Tarlok Singh and 27 other Armed Guards as per New fitment formula w.e.f. 13-2-1992 without giving notice under section 9-A of the ID Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief are the workmen concerned entitled to?"

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.ग्रा. 2481 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012/240/93-आई.आर. (बी-2)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2481.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24-8-95.

[No. L-12012/240/93-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 26 of 1995

In the matter of dispute between :

Zonal Secretary,  
Central Bank of India Employees Union (UP),  
134, F Block Pandi,  
Kanpur.

AND

Regional Manager,  
Central Bank of India,  
Pandu Nagar,  
Kanpur.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/240/93-IR (B-II) dated 24-3-1994, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Kanpur in not paying salary to Shri S. S. Rastogi, Special Assistant for the month of May, 1993 is justified? If not, to what relief, is the said workman entitled to?"

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.



3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.ग्रा. 2482 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/251/94-आई.आर. (बी.-2)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2482.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24th August, 1995.

[No. L-12012/251/94-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 5 of 1995

In the matter of dispute between:

State Vice President,  
Union Bank Staff Association, U.P.,  
362, Nai Basti,  
SITAPUR.

AND

Dy. General Manager,  
Union Bank of India,  
Zonal Office,  
Kapoorthala Complex,  
Aliganj,  
Lucknow.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/251/94-I.R.(B-2), dated 26th December, 1994, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the demand of the Union Bank Staff Assn., UP, Sitapur on the management of Union Bank of India, Lucknow for payment of Special Allowance for Agri., Asst. to Sri Chitaranjan Awasthi, Clerk-cum-Typist w.e.f. 1st June, 1989, is justified. If so, what relief is the workmen entitled to?”

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

2145 GI/95—3

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.ग्रा. 2483 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/290/94-आई.आर. (बी. 2)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2483.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24th August, 1995.

[No. L-12012/290/94-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 18 of 1995

In the matter of dispute between:

Sri P. K. Tiwari,  
State Vice President,  
Union Bank of Staff Association,  
362, Naibasti,  
Sitapur-261001.

AND

Dy. General Manager,  
Union Bank of India,  
Zonal Office,  
Kapoorthala Complex,  
Aliganj,  
Lucknow.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/290/94-I.R.(B-2), dated 12th January, 1995, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the action of the management of Union Bank of India, Lucknow in imposing the punishment of stoppage of one annual increment permanently on Shri Lal Singh, Clerk/Cashier vide their order dated 27th January, 1992, is legal and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?”

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.ग्रा. 2484 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार युनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/321/94-ग्राई.आर.बी.-2]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2484.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 24th August, 1995.

[No. L-12012/321/94-IR(B-II)]  
BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 32 of 1995

In the matter of dispute between :

Sri Amar Saini,  
S/o Sh. Raja Ram,  
Rajaram Tola, Durga Ganj,  
P.O. Kakori,  
District Lucknow.

AND

Dy. General Manager,  
Union Bank of India,  
Zonal Office,  
Kapoorthala Complex,  
Aliganj,  
Lucknow.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/321/94-I.R.(D-2) dated 28th February, 1995, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Union Bank of India, Lucknow in terminating the services of Shri Amar Saini, Casual workman w.e.f. 2nd August, 1992 is legal and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2 In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

3. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of proof. He has not entitled to any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

का.ग्रा. 2485 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. सेंट्रल कोल फील्ड्स लि. की एरा कोलियरी/चैनपुर साइडिंग के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (मं. 2) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या-एल-20012/136/92-ग्राई.आर. (कोल-1)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th August, 1995

S.O. 2485.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Ara Colliery/Chainpur Siding of M/s. Central Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25-8-95.

[No. L-20012/136/92 IR(Coal-I)]  
BRAJ MOHAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD  
PRESENT

Shri D.K. Nayak, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 152 of 1993

Parties : Employers in relation to the management of Ara Colliery/Chainpur Siding of M/s. Central Coalfields Ltd. and their workmen.

Appearances :

On behalf of the workmen Shri J.P. Singh, Advocate.

On behalf of the employers Shri B. Joshi, Advocate.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dated, Dhanbad, the 17th August, 1995

## AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/136/92-I.R. (Coal-I), dated, the 23rd August, 1993.

## THE SCHEDULE

"Whether the management of the Ara Colliery/Chainpur Siding of M/s. C.C.L. At & P.O. Ara, Distt. Hazaribagh is justified in denying the regularisation to the workmen whose names are enclosed in the list attached hereto and the benefits entitled after their regularisation? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2. In this case both the parties appeared and filed their respective W.S. Subsequently both the parties appeared before me and filed a Petition of Compromise. I heard both the parties on the said petition of compromise and I do find that the terms contained therein are fair, proper and legal one. Accordingly I accept the said petition of compromise and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as annexure.

D.K. NAYAK, Presiding Officer

## ANNEXURE

Before the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal No. 2, At Dhanbad

Reference No. 152/93

Employers in relation to the Management of Kuju Siding of Kuju Area of M/s. CC Ltd.

## AND

Their Workmen

Petition of Compromise

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully sheweth :—

1. That the Central Government notification No. L-20012/136/92-IR (Coal-I) dated 23-8-93 has been pleased to refer the present dispute for Adjudication of the Hon'ble Tribunal on the following issues :—

"Whether the management of the Ara Colliery/Chainpur Siding of M/s. CCL at & P.O. Ara, Distt. Hazaribagh is justified in denying the regularisation to the workmen whose names are enclosed in the list attached hereto and the benefits entitled after their regularisation? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

## List of the persons regularisation :

Sl. No.	Name	Designation	To be regularise
S/Shri			
1.	Hemlal Rana	Gr. I Clerk	Loading Inspector
2.	Sarif Khan	Gr. II Clerk	-do-(Dead)
3.	B.N. Tiwari	-do-	-do-
4.	Islam Khan No. II	-do-	Atten. Clerk/Asstt.
5.	Baldeo Rana	-do-	Loading Clerk
6.	Daleswar Pathak	-do-	-do-
7.	Gudeslar Rana	-do-	-do-
8.	K.D. Tiwari	-do-	-do-
9.	Gallu Rana	-do-	-do-
10.	Islam Khan No. I	-do-	Asstt. Loading Inspector
11.	Nirmal Mahto	-do-	-do-
12.	Sri D. Tiwari	Loading Insp.	Sr. Loading Inspector
13.	„ B.C. Mazumdar	-do-	-do-
14.	„ Alimam Hussain	Gr. II Clerk	Asstt. Loading Inspector

List of person who are working as breaker to be regularised in CAT. III :

15. S/Shri Chorta Turi
16. „ Tulsia Bhuiya
17. „ Bigla Turi
18. „ Bigla Bhuiya
19. „ Bartua Turi
20. „ Jiri Mahto
21. „ Agunu Munda
22. „ Barhan Ram
23. „ Jugal Mistry
24. „ Mahabir Manjhi
25. „ Bhola Bhuiya
26. „ Jhaman Saw
27. „ Sanzar Khan
28. „ Saraz Khan
29. „ Nirmal Khan
30. „ Agna Bhuiya
31. „ Pannuwa Turi
32. „ Chandronia
33. „ Sukra Karmali
34. „ Laliya Bhuiya
35. „ Babulal Saw
36. „ Mahabir Karmali
37. „ Bansia Bhuiya
38. „ Jagdeo Bedia
39. „ Rameshwar Ravidas
40. „ Gijra Bhuiya
41. „ Mangthu Bhuiya
42. „ Kuswa Bhuiya

43. Shri Sohra Bhuiya
44. „ Kokil Mahto
45. „ Raman Mehto
46. „ Pranev Das
47. „ Ratna Karmali
48. „ Suguna Bhuiya
49. „ Goura Bhuiya
50. „ Bigan Mahto
51. „ Mukhlal Karmali
52. „ Kunjuwa Bhuiya
53. „ Totra Orawn
54. „ Bitha Karmali
55. „ Bijay Bhuiya
56. „ Samu Bhuiya
57. „ Lalku Munda
58. „ Kisto Munda
59. „ Teju Seth
60. „ Hari Kisto Munda
61. „ Kalim Khan
62. „ Zakir Khan
63. „ Balchand Turi
64. „ Phulchand Munda
65. „ Zabra Karmali
66. „ Chattu Mahto
67. „ Chaman Mia
68. „ Moti Mahto
69. „ Pachu Dhobi
70. „ Natlal Bhuiya
71. „ Karwa Bhuiya
72. „ Kaila Mahto
73. „ Muslim Ansari Cat. I Peon
74. „ Jagan Saw Cat. I Peon
75. „ Dumar Lal Mahto Cat. I Receiving  
Munshi

List of Workman for Payloader Operator :

76. „ Arun Kumar
77. „ Amarjeet
78. „ Bholanath Mahto
79. „ Ghango Bedia
80. „ Birju Chouhan
81. „ Bihari Lal Mahto-3.
82. „ Tepa Mia
83. „ Dhaneshwar Mahto
84. „ Kokil Rajwar
85. „ Keso Mahto

2. That the aforesaid dispute has been amicably settled on the following terms :—

Terms of Settlement

(a) That the concerned workman at Sl. No.1 Sri Hemlal Rana has been regularised as Asstt. Loading Inspector in Gr. C. w.e.f. 23-6-93 and he does not press his earlier demand for the post of loading Inspector.

(b) That the concerned workman at Sl. No. 3 & 14 namely S/Sri B.N. Tiwari and Ali Immam Hussain

will be regularised as Asstt. Loading Inspector in Gr. C after publication of the Award they will have no further claim in this regard in future.

(c) That the concerned workman at Sl. No. 2 & 9 namely S/Sri Sarif Khan and Gullu Rana will have no claim of any kind as they have already expired. The heirs will not raise any demand for their regularisation on the higher post. Similarly the workman at Sl. No. 8 Sri. K.D. Tiwari will not claim as he has already retired.

(d) That concerned workman at Sl. No. 4, 5, 6 & 7 namely S/Sri Islam Khan No. 2, Baldeo Rana, Daleshwar Pathak and Gudeswar Rana shall be regularised as Loading clerk in grade II after publication of the Award. They will have no further claim of any kind.

(e) That concerned workman at Sl. No. 12 & 13 namely B. Tiwari and B.C. Mazumdar will be regularised as Sr. Loading Inspector in Gr. A after publication of the Award. They will not have any further claim on account of regularisation.

(f) That the concerned workman at Sl. No. 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 55, 56, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71 & 72 namely S/Shri Tulsia Bhuiya, Bigla Turi, Jiri Mahto, Barhan Ram, Mahabir Manjhi, Bhola Bhuiya, Sanzar Khan, Saraz Khan, Nirmal Khan, Agna Bhuiya, Pannua Turi, Lalia Bhuiya, Babulal Saw, Mahabir Karmali, Banshia Bhuiya, Jagdeo Bedia, Mangthu Bhuiya, Kusuwa Bhuiya, Kokil Mahto, Reman Mahto, Suguna Bhuiya, Bigan Mahto, Mukhlal Karmali, Bijay Bhuiya, Samu Bhuiya, Kalim Khan, Zakir Khan, Chattu Mahto, Chaman Mian, Pachu Dhobi, Natlal Bhuiya, Karwa Bhuiya, and Kali Mahto respectively have been regularised as Time rated workers in Category-I with effect from 1-1-90 and Category III with effect from 30-12-94. They do not have any further claim in this regard.

(g) That the concerned workmen at Sl. No. 15, 18, 21, 23, 33, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 65 & 68 namely Sri Chorta Turi, Bigala Bhuiya, Agnu Munda, Jugal Mistry, Sukra Karmali, Raita Karmali, Lalku Munda, Kinto Munda, Teju Seth, Harikisto Munda, Balchand Turi, Zabra Karmali and Moti Mahto have not yet been regularised as T/R worker as they have not completed 240 days of attendance in any Calendar year on T/R jobs. Their cases will be considered for regularisation when they will fulfil the criteria for regularisation in future. They do not press any demand for their regularisation at present.

(h) That the concerned workmen at Sl. No. 39, 47, 52 & 53 namely Rameshwar Rabides, Ratna

Karmali, Kunjuwa Bhuia and Tetra Orawn have already expired and they will have no claim for their regularisation.

(i) That the concerned workmen at Sl. No. 26-32, 40, 46, 49 & 64 namely S Sri Jhemam Saw Chandronia, Gijra Bhuia, Pranav Das, Gaura Bhuia, Kunjuwa Bhuia and Phulchand Munda have already retired under V.R.S. and they do not have any claim with regard to their regularisation.

(j) That the concerned workmen at Sl. No. 73 namely Muslim Ansari has already been regularised as peon w.e.f. 25-6-93 and he will have no further claim with regard to his regularisation. The workmen at Sl. No. 74 namely Sri Jagan Saw will be regularised as peon in future when vacancy will arrive. He will have no claim for his regularisation as Peon at present.

(k) That the concerned workmen at Sl. No. 75 namely Sri Dumar Lal Mahto will not claim for his regularisation in Clerical Cadre in Gr. III as he is not a Matriculate. His case will be considered after he obtains his Matriculation certificate.

(l) That the concerned workmen at Sl. No. 82 namely Sri Tepa Mian has already been regularised as PAY LOADER OPERATOR, in Gr. 'B' and he will not have any further claim in this regard.

(m) That the concerned workmen at Sl. No. 11, 78, 80, 81 & 85 namely Nirmal Mahto, Bhola Nath Mahto, Birju Chuhan, Bihari Lal Mahto & Keso Mahto, have no claim for their regularisation as Pay Loader as they have been transferred to Ara.

(n) That the concerned workmen at Sl. No. 76, 77, 79, 83 and 84 namely Sri Arun Kumar, Amarjit, Chango Bedia, Dhaneshwar Mahto and Koki Rajwar, will have no claim for their regularisation as Pay Loader Opr. at present. Their cases will be considered in future on Merit after existence of vacancies alongwith others.

(o) That the concerned workmen at Sl. No. 10 namely Islam Khan No. 1 will have no claim for his regularisation as Asstt. Loading Inspector. His case will be considered in future on Merit after existence of vacancies.

3. That in view of the above settlement there remains no dispute for adjudication.

Under the facts and circumstances, it is humbly prayed that the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the terms of settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

*For the workmen :*

1. Sd/-  
Illegible

2. Sd/-  
Illegible

*For the employer :*

1. Sd/- Illegible  
Agent/Project  
Officer,  
Kuju Siding,  
C.C.L.

2. Sd/- Illegible  
General Manager  
(K), Kuju Area

**Witness :**

1. Sd/-

2. Sd/-

Presiding Officer,  
Central Govt. Industrial Tribunal (No. 2),  
Dhanbad.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1995

का.आ. 2486:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यू.पी. स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/84/95-आई आर (विवाद)]  
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th August, 1995

S.O. 2486.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of U.P. State Mineral Development Corporation Ltd. and their workmen, which has received by the Central Government on the 25-8-1995.

[No. L-29012/84/94 IR(Misc.)]  
B. M. DAVID, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL  
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 34 of 1995

In the matter of dispute between :

Sri Vijay Pratap Singh  
C/o Sri Anil Kumar Srivastava,  
69/5 Sonbatia Bag,  
Allahabad.

AND

Pariyojana Prabandhak,  
U.P. State Mineral Development Corporation Ltd.,  
2/3, Circular Road,  
Allahabad.

## AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-29012/84/94-I.R. (vividh) dated 7-3-95, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the action of the management of U.P. State Mineral Development Corporation in terminating the services of Shri Vijay Pratap Singh S/o Shri Jai Ram Singh vide their order No. MDC/AI/PM/88-89/1061 dated 3-11-88 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. In spite of repeated opportunities having been given to the concerned workman, he neither filed any claim statement nor put in appearance in the Tribunal. It appears that he is not interested in the case.

2. Hence my answer to the reference is in the affirmative and against the concerned workman for want of Proof. He has not entitled to any relief.

3. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली. 29 अगस्त, 1995

का.आ. 2487 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंदोर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 28-8-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/73/86-डी-II (ए)/आईआरबीआई]

पी.जे. माइकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th August, 1995

S.O. 2487.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Indore and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th August, 1995.

[No. L-12012/73/86-DII(A)/IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL  
CUM LABOUR COURT, PANDU NAGAR DEOKI  
PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 8 of 1987

In the matter of dispute between :

The State Assistant General Secretary U.P. Bank Employees Union 36/1 Kailash Mandir, Kanpur.

And

The Branch Manager, State Bank of Indore, Gumti No. 5, Kanpur.

## AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-12012/73/86-D.II(A) dated 13th

January, 1987 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

“Whether the action of the management of State Bank of Indore Gumti No. 5, Kanpur in reverting S/Sri A. N. Srivastava, Cashier and A. K. Awasthi, clerk-cum-cashier to the post of peon and peon-cum-lairash respectively w.e.f. 26-8-85 is justified? If not, to what relief the concerned workman are entitled?”

2. This reference relates to two workmen viz., A. N. Srivastava and A. K. Awasthi. Both of them were working as peon in the opposite party State Bank of Indore Gumti No. 5, Branch Kanpur.

3. The case of A. N. Srivastava is that he was promoted to the post of cashier on 20-8-83 and worked there upto 26-6-85 continuously. As he had worked for more than six months on this regular post he was entitled to become permanent. During this tenure washing allowance which he had drawn in the capacity of peon was recovered and further he was required to furnish cash security of Rs. 1000. This incident lead to the conclusion that he was promoted on a permanent post.

3. The case of Sri A. K. Awasthi is that he was promoted on the post of cashier/clerk on 9-11-82 and he worked there till 29-6-85. Although he was doing regular work he was designated as officiating. He too should be deemed to have been confirmed on this post after serving six months. The bank has contravened the provisions of Bipartite Settlement by not confirming him. Both of them have further alleged that their reversion order w.e.f. 30-6-85 is bad in law as the same cannot be done without holding any enquiry.

4. Opposite party has submitted their reply. The substance of which is that as and when vacancy arose these two persons were allowed to officiate as no other hand was available. Further they were paid officiating allowance and that they were never promoted. As a matter of fact there is a procedure for promotion without which a person cannot be deemed to be promoted.

5. The concerned workman have filed rejoinder in which nothing new has been said.

6. As regards the case of A. K. Awasthi, it may be mentioned that neither he nor any one in his behalf had entered in the witness box to substantiate his claim. Even A. N. Srivastava as witness has said nothing about A. K. Awasthi. Hence his entire claim has to be negatived for want of proof.

7. As regards A. N. Srivastava, he himself has entered into witness box to say that he had continuously worked. However, in his cross examination he had stated that he was not given any promotion order.

8. On the other hand Priyam Kumar Lal and Pradeep Joshi have filed affidavits on behalf of management. Pradeep Joshi had proved documents such as attendance register etc., in which the concerned workman has described himself as peon and not as cashier during relevant period. This factor goes to long way in falsifying the claim of the concerned workman. Apart from it Priyam Kumar Lal in his affidavit has given full details of the days on which A. N. Srivastava had worked in place of persons who had proceeded on leave. This evidence shows that the concerned workman had not continuously worked. Instead he had worked in place of some official who had proceeded on leave. Such working in place of some one is nothing but officiation. The concerned workman had also filed documents relating to his claim for promotion. In my opinion, these papers in no way further the claim of the concerned workman. Thus, taking into consideration the documents and evidence of Priyam Kumar regarding details of days for which the concerned workman had worked as clerk and also his conduct describing himself as peon, I come to the conclusion that the concerned workman was not promoted. Instead he was asked to officiate for which he was given officiating allowance. Hence, it cannot be said that the concerned workman was promoted at all. As such no question of his

reversion from the promoted post arises. If the management had chosen not to provide him officiating post, it cannot be said to be unjustified.

8. In view of above discussion, the reference is rendered meaning less as a person cannot be reverted from the post which he had not held at all.

9. Hence reference is answered in the affirmative and consequently both the workmen are entitled for no relief.

10. Reference is awarded accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1995

का.आ. 2488.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सीमेंट उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 3 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाओं में घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/13/85-डी-1(ए)]

एस. वेणुगोपालन, अवसर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1995

S.O. 2488.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Cement Industry which are covered by entry 3 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purpose of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/13/85-D.I(A)]

S. VENUGOPALAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1995

का.आ. 2489.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (VI) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 746 दिनांक 2 मार्च, 1995 द्वारा बैंकिंग उद्योग को जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख)

में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी द्वारा चलाया जाता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मार्च, 1995 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 सितम्बर, 1995 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/2/85-डी 1(ए)]

एस. वेणुगोपालन, अवसर सचिव

New Delhi, the 31st August, 1995

S.O. 2489.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 746 dated the 2nd March, 1995, the Banking Industry carried on by a Banking Company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act to be a public utility service for the purpose of the said industry, for a period of six months from the 19th March, 1995;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 19th September, 1995.

[No. S-11017/2/85-D.I(A)]

S. VENUGOPALAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1995

का.आ. 2490.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (VI) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 682 दिनांक 23 फरवरी, 1995 द्वारा

भारत प्रतिभूति मन्त्रालय, गान्धिक को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 12 मार्च, 1995 में छह मास की कालावधि के लिए लोक उद्योगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (इ) के उपखंड (IV) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 12 मिनम्बर, 1995 में छह मास की और कालावधि के लिए लोक उद्योगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस 11017/3/91 आई.आर. (पालिसी विधायी)]  
एस. वेणुगोपालन, अवसर सचिव

New Delhi, the 31st August, 1995

S.O. 2490.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 582 dated 23rd February, 1995, the India Security Press, Nasik to be a public utility service for the purposes of the said Act. for a period of six months, from the 12th March, 1995;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six month from the 12th September, 1995.

[No. 11017/3/91-IR(PL)]

S. VENUGOPALAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1995

का.आ. 2491.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर

के पंचवट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-8-95 को प्राप्त हुआ था —

[स. एन 22012/266/90 आई आर सी II]

राजालाल, डेस्क का अधिकारी

New Delhi, the 31st August, 1995

S.O. 2491.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-8-1995.

[No. L-22012/266/91-IR C II]

RAJA LAL,, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SRI B.K. SRIVATAVA PRESIDING  
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT IN-  
DUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR  
COURT PANDU NAGAR DEOKI PALACE  
ROAD KANPUR.

Industrial Dispute No. 12 of 1991

In the matter of dispute between :

State Secretary,  
Bhartiya Khadya Nigam Karamchari Sangh,  
5-6 Habibulla Estate,  
Lucknow.

AND

Senior Regional Manager,  
Food Corporation of India,  
5-6 Habibulla Estate  
Lucknow.

#### AWARD :

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-22012-(266)/90 IR (C?) dated 15-2-1991, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

Whether the Sr. Regional Manager, F.C.I. was justified in imposing penalty of the increment with commulative effect vide his order dt. 31-3-90 and also reversion of Sri Savita from AG.I to AG.II w.e.f. 31-12-87 ? If not to what relief the workman concerned is entitled.

2. The instant reference comprises of the parts. The first part relate to the punishment of the concerned workman R. P. Savita resulting from domestic enquiry. The second part pertains to illegality of his reversion from the post of AG.I to AG.II.



3. Now facts regarding to the punishment of stoppage of one increment cumulative effect may be considered.

4. The concerned workman was originally appointed as watchman in the opposite party in Food Corporation of India in 1961. He was promoted to the post of A.G. Grade III on 27-1-68 and further to the post of A.G. II on 15-6-76. He was further promoted to the post of A.G. Gr. I on 30-11-87. On 31-12-88, the concerned workman while working as A.G.I. was served with the following charge:—

Charge—

Sri R. P. Savita, AG. II(D) while posted and functioning as such at FSD, Farrukhabad during 1986 failed to maintain absolute, incereely, honesty, integrity, devotion to duty and acted in a manner of unbecoming of corporation employee in as much as he embazzled/misappropriated FCI Funds|Articles by manipulating records and with unfair intention to cover up his guilt and misdeed, he arranged|managed by lodging at false FIR with Police for theft allegedly occured in the night of 3|4-5-88. The police closed the case after conducting detailed investigation being worth less and unestablished case of theft.

Thus said Sri R. P. Savita, AG.II (D) misrepresented the fact, and attempted to cheat the corporation by concealing facts and thereby contravened regulation 31 and 32 of FCI Staff Regulation, 1971.

The concerned workman submitted his reply alleging that he has not embazzled the amount. Instead a dacoity had taken place in the night intervening 3|4-5-88, and in that course the amount in question was taken away by miserients. It may be mentioned that before initiation of enquiry, the matter was got investigated by two officers vix. A. K. Shukla, and B. P. Kapoor A, M Manager. They in their report had found that the concerned workman was responsible. They had not taken into consideration the version of the concerned workman on the ground that the matter was under investigation by the police. During the course of enquiry A. K. Shukla Asstt. Manager and one H. S. Tripathi were examined. Besides 10 documents were also filed. In defence the concerned workman examined Chowkidar Ratiram Sagar as D.W.I beside 4 documents were filed. The enquiry officer J. C. Pandey Dy. General Manager, in his report dt. 30-8-89, has found that the charged was proved. On the basis of this report, Senior Regional Manager in the capacity of disciplinary authority in his order dt. 30-9-90 inflicted the punishment of stoppage of one increment with cumulative effect. Feeling aggrieved by this punishment, the

concerned workman has raised the instant industrial dispute through the Union.

5. As regards the case of reversion, it was alleged that he was promoted to the post of Asstt. Gr. I from the post of Asstt. Gr. II by order dated 30-12-87 and he took charge on 31-12-87. The management opposite party without assigning any reason or holding enquiry had reverted him to the post of Assistant Gr. II by order dated 14-1-88 which is illegal. Hence dispute in this regard has also been referred.

6. In the claim statement the concerned workman has challenged the validity of enquiry on the ground that the charges were not properly framed and that he was not provided with the documents. It was also alleged that in any case findings of the enquiry officer are not against the concerned workman. It was also alleged that the concerned workman was illegally reverted from the post of Assistant Gr. I to the post of Asstt. Gr. II by order dated 14-1-88.

7. In the written statement the employer has denied all the allegations.

8. In the rejoinder nothing new has been said.

9. First it will be considered if the enquiry was fairly and properly held. I have gone through the charge in which it has been clearly alleged that the concerned workman has misappropriated Rs. 10000 and had lodged a false F.I.R. for theft in order to save his skin. It will be evident that charge is quite explicit and admits of no ambiguity. Hence, nothing can be said about it. It was also alleged in the written statement that enquiry officer did not furnish him the require documents by way of defence. It is true that during the course of enquiry the concerned workman had asked for certain documents, some of them were supplied and some of them could not filed being not available. The details of these papers have not been disclosed either in the enquiry file or in this Tribunal. Hence, it cannot be judged if by not filing those papers the case of the concerned workman has been prejudiced or not. It is well settled law that simply failure to supply papers to the delinquent the course of enquiry would not vitiate the enquiry. It will be rendered vitiated only when prejudice is chown which in the instant case has not been done. Hence on this score also the enquiry will not be rendered defective. No other point has been alleged regarding invalidity of enquiry report. Thus repelling the contention of the authorised representative of the concerned workman, it is found that the enquiry officer had held the enquiry according to Regulation 58 of FCI (Staff) Regulation 1971 and as such is not vitiated.

10. Now it will be seen if the findings is perverse. I have gone through the report of the en-

quiry officer. Although there is mention that evidence of Ratiram Sagar D.W. 1 but there is no discussion in respect of the evidence in his report. It has not been made clear as to why evidence of serving chowkidar D.W. 1 has not been accepted. Since in my opinion, the evidence of Ratiram Sagar was supported by prompt F.I.R., his evidence could not be easily brushed aside. At least the defence version was probalised. Further in my opinion, the case of the management too was not independently proved as evidence of A.K. Shukla and Tripathi was not based on their personal knowledge. It was necessary that evidence of such person of the locality should have been produced who could have been in a position to speak on the basis of their personal knowledge that no such incident in the night intervening 3/4-5-86 had taken place. I am further of the view that because of inability of police to work out the case, the version of the concerned workman cannot be said to be false. Taking into consideration the totality of the facts, I am of the opinion that there was substance in the version of the concerned workman that in the night intervening 3/4-5-86 miscreants has entered in the office and had taken the money and perhaps that is why the enquiry officer in his report has not held that the concerned workman had actually misappropriated Rs. 10,000. Instead he was held to be entirely responsible.

11. Thus in view of foregoing discussions, I am of the view that the findings of the enquiry officer is perverse.

12. The authorised representative for the management has with reference of imprest register has argued that in this register the concerned workman has indulge manipulation to fulfill his desire of misappropriation of Rs. 10,000. It need not be looked into as there is no charge against the concerned workman regarding manipulation of record.

13. There is another aspect of the case. As has been noted earlier the enquiry officer has held that the concerned workman was responsible for loss of Rs. 10,000, in any opinion from this finding the charge of misappropriation of Rs. 10,000 is not proved. There may be case where a person may be responsible for loss of money as he may not be having any criminal intent to embezzel the and money. On the other hand there may be case where the delinquent may be having criminal intent to misappropriate the money. In any case both the illustrations are not synonymous.

14. As such on the basis of findings of enquiry officer also the charge of misappropriate does not stand proved. From this point of view also punishment has been wrongly inflicted.

15. I have gone through the contents of written statement of the management. It has nowhere been prayed that in the event of enquiry report

being found vitiated the management may be given opportunity to prove the charge on merits before this Tribunal. In the case of Shambhu Nath Goel Versus Bank of Baroda 1983(4) SCC 491 the management cannot be given opportunity in this tribunal to prove the charge on merits. As such the enquiry report having been found to be vitiated and further charge being not proved, I come to the conclusion that the management was not justified in imposing punishment of stoppage of one increment with cumulative effect w.e.f. 31-3-90.

16. Now the second part of the reference may be considered. It is common ground that promotion order of the concerned workman from the post of AG Gr. II to A.G. Gr. I was passed on 30-12-87 and actually he took charge on 31-12-87. It is also admitted to the management that the concerned workman was reverted by order dt. 14-1-88. In para 11 of the written statement it was alleged that the workman was reverted as he had manipulated to join his duties as AG Gr. I and had not completed the required formalities in this regard. Further there was vigilance enquiry against him. Now we may look to promotion order. The copy of this promotion order annexure 9 to list paper No. 3/2. The opening part of this order runs as under:—

In pursuance to the Zonal Office (N) order No. 167/87 issued from file No. 2/44/87/E. JLNZ/PT/APR dated 30-12-87 and dated 30-12-87 following A.G. II (D) and A.G. III (D) are promoted to the post of A.G. I (D) and A.G. II(D) in the pay scale of Rs. 450-15-555-20-675 25-850 and 380-12-450-15-560-20-640 respectively on purely adhoc basis without prejudice to the claim of senior to them and subject to decision of Hon'ble High Court/Supreme Court/PB and Hon'ble High Court and J&K High Court.

This order is without prejudice to the regular avenue of promotions and hence the promotion made are purely temporary and officials are liable to be reverted without any notice. This order will not confer them any right either in regard to seniority in the present grade or in further promotions on regular basis.

A bare perusal of the above recital would show that the promotion of the concerned workman was without any rider. There is no evidence on record to show that the concerned workman in any way had indulged in manipulation of joining report. Further there is no reference that his promotion was subject to clearance by vigilance department. Instead in normal course when a person is promoted his previous record is scrutinised and it is also ascertained if any vigilance enquiry is pending before passing of promotion order. If the promotion order is passed it is deemed that he was free

from all short comings. In this context in my opinion, there is no good ground for reverting the concerned workman. In any case due enquiry ought to have been held before reversion. As such my findings is that the action of the management in reverting the concerned workman from the post of A.G. Gr. I to the post of A.G. Gr. II is not justified. Consequently he will be entitled for promotion to A.G. Gr. I w.e.f. from the date of his reversion with all consequential benefits.

In the end my finding to first part of the reference order is that the action of the management in imposing the penalty of stoppage of one increment with cumulative effect is not justified and as such after ignoring this order the concerned workman will be entitled for all consequential benefits. Further the order of reversion is set aside and the concerned workman will be entitled for all financial benefits. The concerned workman shall also got Rs. 200 as costs from the opposite party.

Reference is answered accordingly.

Dt. 8-8-1995.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1995

का.आ. 2492.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण, में सरकार एस.ओ.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 अगस्त, 1995 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/427/93 आई आर (सी II)]  
राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st August, 1995

S.O. 2492.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-8-1995.

[No. L.22012/427/93-IR (CII)]

RAJA LAL, Desk Officer

## ANNEXURE

### BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, HYDERABAD-II, AT HYDERABAD

PRESENT :

SHRI E. ISMAIL, B.Sc., LL.B.,  
CHAIRMAN

Dated : 17th June, 1995.

I. D. NO. 11/94

(CENTRAL)

BETWEEN :

The Secretary,  
Singareni Coal Mines Karmika Sangam.  
(Affiliated B.M.S.)  
H. No. C-81, Near Andhra Bank,  
Godavari Khani,  
Karim Nagar, District,  
Andhra Pradesh.

Petitioner

AND

The General Manager,  
B.C.C. Limited,  
R. G-III, Godavari Kham,  
Karim Nagar,  
Andhra Pradesh.

Respondent

APPEARANCES :

No representation for Petitioner.

Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate for Respondent.

## AWARD

This is reference made Under Section 10(1)(d) of Industrial Disputes Act, 1947, by Government of India by its order No. L-22012/427/93-I.R. (G.II) from Ministry of Labour, New Delhi dated 21-4-1994 for adjudication of an Industrial Dispute annexed as follows:—

“Whether the Management action is not promoting Sri B. Krishna Rao to the post of Chargehand & (Technical and Supervisory) Grade ‘C’ on par with Sri P. Satyanarayana Rao and 9 others who have secured lower rank than him in order of merit is legal and justified?

If not, what relief the workman is entitled to?”

This case has been referred to this Tribunal for disposal and it is numbered as I.D. 11/94. Thereafter notices have been issued and management notice served. Petitioner notice unserved and returned with postal endorsement that “Office door looked return to sender” on 27-7-94 petitioner called absent. No representation. Issue fresh notice to petitioner through R.P. by 22-8-1994. Petitioner's notice served and Acknowledgement received. Again this case was posted to 19-9-1994 for filing Claim statement. Thereafter three more notices were issued by granting number of adjournments from time to time till 17-6-1995 for petitioner's appearance. Finally to-day i.e., on 17-6-1995 peti-

tioner absent he is not evincing any interest in spite of notice is being served on 22-8-1994. Hence reference is closed.

In the result a Nil Award is passed.

Written by me given under my hand and the Seal of this Tribunal. This is the 17th day of June, 1995.

E. ISMAIL, Chairman  
APPENDIX OF EVIDENCE

No oral or documentary evidence has been adduced by either side.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1995

का.आ. 2493.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16-9-1995 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला महसाणा के कलोल तालुक में राजस्व ग्राम छत्तराल, बिलेश्वरपुरा, धनोट जी.आई.डी.सी. इस्टेट छत्तराल के क्षेत्रों सहित तथा वह क्षेत्र जिन्हें गुजरात सरकार के इण्डस्ट्रीज एण्ड माईन्स विभाग की अधिसूचना संख्या : जी.एच.यू. 93(31) जी.आई.डी-1690-243, जी.आई. दिनांक 6-9-93 एवं गुजरात राज्य सरकार के डिबेलपमेंट कमिशनर की अधिसूचना संख्या के.पी.बी./72 बीबीएन/पी.1 दिनांक 6-9-93 के द्वारा घोषित “अधिसूचित क्षेत्र की राजस्व एवं पंचायत सोमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

[सं. एस-38013/56/95एस एस. 1]

जे. पी. शुकला, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1995

S.O. 2493.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th September, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat namely:—

“Within the revenue and Panchayat limits of Village Chhatral, Bileshwarpura, Dhanot including the areas of G.I.D.C. Estate Chhatral and the area declared as “Notified Area” by the Industries and Mines Department Government of Gujarat vide Government Notification No. GHU-93(31) GID-1690-243 GI dated

6-9-1993 and Notification No. KPV/72/VBN/P1 dated 6-9-1993 issued by the Development Commissioner, Government of Gujarat in Taluka Kalol, District Mehsana.”

[No. S-38013/56/95-SS. II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर 1995

का.आ. 2494.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16-9-95 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व धाना की संख्या	जिला
1.	2.	3.	4.
देवघर			
1.	महेश्वारा	250	देवघर
2.	नन्धन पहाड़	252	देवघर
3.	बरमसिया	254	देवघर
4.	मधुसदन छारेट	255	देवघर
5.	मदारी चक	256	देवघर
6.	बेला बगीचा	257	देवघर
7.	हिरना	269	देवघर
8.	सुरतीलोना	270	देवघर
9.	बासमता	276	देवघर
10.	कल्याणपुर	398	देवघर
11.	पुरनवाहा	399	देवघर
12.	बरियार बोची	400	देवघर
13.	टोराडिह	401	देवघर
14.	खरादात	402	देवघर
15.	कुण्डा	409	देवघर
16.	नीलकण्ठपुर	415	देवघर
17.	साहरजोर	416	देवघर
18.	जटही	418	देवघर
19.	करहनीबाव	584	देवघर
	जसीडिह		देवघर
20.	जसीडिह बाजार मौजा	119	देवघर
21.	बसुआडिह मौजा	198	देवघर
22.	बाधमारा	199	देवघर
23.	रामचन्द्रपुर	202	देवघर
24.	मेमरिया	203	देवघर

1	2	3	4
25.	ख्वासडीह	263	देवघर
26.	नारायणपुर	262	देवघर
27.	फूटा बांध	027	देवघर
28.	गंगटी	209	देवघर
29.	छोटा मानिकपुर	116	देवघर
30.	बदलाडिह	117	देवघर
31.	तावाघाट	208	देवघर
32.	रामडीह	122	देवघर

[मं. एम. 38013/51/95-एस एम I]  
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1975

S.O. 2494.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th September, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Bihar namely :—

Sl. No.	Name of Revenue Village	No. of revenue thana	District
1	2	3	4
<b>Deoghar</b>			
1.	Maheshwara	250	Deoghar
2.	Nandan Pahar	252	Deoghar
3.	Barmasiya	254	Deoghar
4.	Madhusudan Chhorat	255	Deoghar
5.	Madharichah	256	Deoghar
6.	Bela Bagicha	257	Deoghar
7.	Hirna	269	Deoghar
8.	Surtilona	270	Deoghar
9.	Basmata	276	Deoghar
10.	Kalyanpur	278	Deoghar
11.	Purandaha	399	Deoghar
12.	Bariar Bochi	400	Deoghar
13.	Toradih	401	Deoghar
14.	Kharadat	402	Deoghar
15.	Kunda	409	Deoghar
16.	Nilkanthpur	415	Deoghar
17.	Shaharzor	416	Deoghar
18.	Jatabi	418	Deoghar
19.	Karhanibad	584	Deoghar

**Jasidih :**

20.	Jasidih Bazar Mauja	119	Deoghar
21.	Basuadih Mauja	198	Deoghar
22.	Baghmara	199	Deoghar
23.	Ramchandrapur	202	Deoghar
24.	Semariya	203	Deoghar
25.	Khwasdih	263	Deoghar
26.	Raidih	122	Deoghar
27.	Narainpur	262	Deoghar
28.	Phootabandh	27	Deoghar
29.	Gangati	209	Deoghar
30.	Chhota Manikpur	116	Deoghar
31.	Badaladih	117	Deoghar
32.	Tawaghat	208	Deoghar

[No. S-38013/51/95-SS.I]  
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1995

का.प्रा. 2495.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16-9-1995 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे अर्थात् :—

“जिला धरमापुरी के तालुक धरमापुरी में धरमापुरी नगरपालिका की नगरपालिका सीमाएं एवं राजस्व ग्राम अधियासन कोटाई, थाइनगाम ब्रेलगुन्डमपालायम, पापीनाईकानाहल्ली, नालनाहल्ली धीरूपक्षीपुरम ए. जेट्टीहल्ली ए. रेड्डीहल्ली और पालाकोड तालुक में राजस्व ग्राम बायसुहल्ली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[संख्या एस-38013/52/95-एसएस-1]  
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1995

S.O. 2495.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th September, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said

Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely:—

Areas comprising the Municipal limits of Dharamपुरी Municipality, and the Revenue Villages of Adhiyamankottai, Thadangam, Vellagondampalayam, Pappinaickanahalli, Nallanahalli, Virupakshipuram, A. Jettihalli, A. Reddihalli in Taluk Dharamपुरी and Revenue Village Bysuhalli of Palacode Taluk in District Dharamपुरी.

[No. S-38013/56/95-SS. II]  
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1995

का.आ. 2496.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16-9-95 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे अर्थात् :—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना की संख्या	जिला
1	2	3	4
1.	मेहरपुर	97	बिहार शरीफ
2.	सिपाह	95	बिहार शरीफ
3.	हुजूरपुर	98	बिहार शरीफ
4.	रामपुर बगनाबाद	110	बिहार शरीफ
5.	चक हाजैन	126	बिहार शरीफ
6.	देवी सराय	127	बिहार शरीफ
7.	सलेमपुर	133	बिहार शरीफ
8.	सोहदीह	140	बिहार शरीफ
9.	बाबरबान्ना	141	बिहार शरीफ

[संख्या : एम-38013/54/95-एस एस-1]  
जे. पी. शुकला अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1995

S.O. 2496.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government, hereby appoints the 16th September, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been

brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Bihar namely :—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Revenue Thana No.	District
1	2	3	4
1.	Meharपुर	97	Bihar Sharif
2.	Sipah	95	Bihar Sharif
3.	Hujurपुर	98	Bihar Sharif
4.	Rampur Bagnabad	110	Bihar Sharif
5.	Chak Hajain	126	Bihar Sharif
6.	Devi Sarai	127	Bihar Sharif
7.	Salempur	133	Bihar Sharif
8.	Sohdih	140	Bihar Sharif
9.	Babarbanna	141	Bihar Sharif

[No. S-38013/54/95-SS. I]  
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1995

का.आ. 2497.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16-9-1995 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे अर्थात् :—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना की संख्या	जिला
1	2	3	4
1.	मिठानपुर लाल्ला	410	मुजफ्फरपुर
2.	कनहीनी बिमुनदत्त	411	मुजफ्फरपुर
3.	हरकुल लहुरी	480	मुजफ्फरपुर
4.	कोहलूआ पेगम्बरपुर	482	मुजफ्फरपुर
5.	अयरदाह सलेहपुर बुधन	342	मुजफ्फरपुर
6.	बेला छपरा	281	मुजफ्फरपुर
7.	कनहीनी अगनेकबे	412	मुजफ्फरपुर
8.	छपरा कोटी	352	मुजफ्फरपुर

[संख्या : एम-38013/53/95-एस एस-1]  
जे. पी. शुकला अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 1995

शुद्धि-पत्र

S.O. 2497.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th September, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Bihar namely :—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Revenue Thana No.	District
1.	Mithanpur Lalla	410	Muzaffarpur
2.	Kanhauli Bisundatt	411	Muzaffarpur
3.	Harkul Lahuri	480	Muzaffarpur
4.	Kohlupayagamberpur	482	Muzaffarpur
5.	Athardah Salehpur Budhan	342	Muzaffarpur
6.	Bela Chapra	281	Muzaffarpur
7.	Kanhauli Agnekbe	412	Muzaffarpur
8.	Chapra Lodi	352	Muzaffarpur

[No. S-38013/53/95-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995

का.भा. 2498.—भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3 उप-खंड (ii) में दिनांक 3-6-1995 को का.भा. सं. 1525 के रूप में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 24-4-1995 की अधिसूचना सं. 14012/28/92-आई.आर. (डी. यू.) में उल्लिखित "गन कैरिज फैक्टरी" शब्दों को "आयुध कारखाना, खामरिया, जबलपुर" पढ़ा जाये।

[सं. एल-14012/28/92—आईआर. (डी. यू.)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th September, 1995

S.O. 2498.—In this Ministry's Notification No. 14012/28/92-IR(DU) dated 24-4-1995, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of Gazette of India dated 3-6-1995 as S.O. No. 1525, the words 'Gun Carriage Factory' appearing in the Notification may please be read as "ORDNANCE FACTORY, KHAMARIA, JABALPUR."

No. L-14012/28/92-IR(DU)  
K. V. B. UNNY, Desk Officer

